सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सफलता की ख़ुशी मनाना अच्छा है पर, उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना !

वर्ष 01, अंक 201, नई दिल्ली

मंगलवार, 03 अक्टूबर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

भारत को पेट्रोल-डीजल के चक्रव्यूह से मिलेगा छुटकारा ?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रणनीति का किया खुलासा

नितिन गडकरी ने पेट्रोल–डीजल के इस्तेमाल को खत्म करने की रणनीति बताई.

संजय बाटला, सम्पादक

नितिन गडकरी ने भारत में पेट्रोल–डीजल के इस्तेमाल को खत्म करने की सरकार की रणनीति का खुलासा किया है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से होने वाले दिल्ली प्रदूषण के बारे में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि नागपुर में सभी वाहन बायो–सीएनजी से चल रहे हैं. अब हमारे किसान न सिर्फ हमें खाना खिलाएंगे बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करेंगे.

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने भारत में पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल को खत्म करने की सरकार की रणनीति का खुलासा किया है. चेक गणराज्य के आधिकारिक दौरे पर गए गडकरी ने मंगलवार को प्राग में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत की. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से होने वाले दिल्ली प्रदूषण के बारे में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि ' हमने 186 संयंत्र डिजाइन किए हैं जो पराली से बायो-सीएनजी और बायो-एलएनजी बना सकते हैं. 186 में से 36 संयंत्र मौजूदा वक्त में चालू हैं.' गडकरी ने कहा कि 'नागपुर में सभी वाहन जैसे ट्रैक्टर, बसें और कारें बायो-सीएनजी से चल रही हैं' मेरा एक सपना है कि भारत को पेट्रोल और डीजल से छुटकारा दिलाया जाए' इसे हासिल करना एक कठिन सपना है लेकिन असंभव नहीं है.'

नितिन गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल की एक नई इंडस्ट्री खुली है जो धान की पराली से बिटुमिन और इथेनॉल बनाएगी. पराली से 1,00,000 लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन हासिल किया जा सकता है. भारत को 80 लाख टन बायो बिटुमेन की जरूरत है, जिसमें से 50 लाख टन का लक्ष्य भारतीय रिफाइनरियों से हासिल किया जाता है और 30 लाख टन आयात किया जाता है. अब हमारे किसान न सिर्फ हमें खाना खिलाएंगे बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करेंगे.

इसके अलावा गडकरी ने शहरी विस्तार रोड 2 के बारे में भी जानकारी शेयर किया, जिसके अगले 2-3 महीनों में लॉन्च होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में नए रास्ते से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक पहुंचने का समय 2 घंटे से घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा. उन्होंने कहा कि 'हमने एक और सुरंग वाली सड़क बनाई है जो हवाई पट्टी के नीचे से आईजीआई हवाई अड्डे के टी3 तक जाती है.' दिल्ली में नई अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 अटल सुरंग की तरह है.

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Fornt Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

डीटीसी पेंशनर्स, मार्शल,ओपीएस सब सडकों पर

डीटीसी के मार्शलों को भी पिछले चार पांच महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। ये जवान भी जिनमें महिलाएं भी शामिल है।

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर डीटीसी के रिटायर्ड बुजुर्ग अपनी पेंडिंग चल रही तीन-से चार महीनें की पेंशन की मांग को लेकर राजधानी की सडकों पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।

पेंशन ना मिलने से बीमार और लाचार बुजुर्ग अपनी दवा और तीमारदारी के भी मोहताज हो गए हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स दिल्ली के सीएम से लेकर तमाम दरबारियों के चौखटों पर अपना सिर पटक चुके हैं ।हालात ये हैं कि बुजुर्ग पेंशनर्स की सुनने वाला कोई नहीं है ।

इसी कडी में डीटीसी के मार्शलों को भी पिछले चार पांच महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। ये जवान भी जिनमें महिलाएं भी शामिल है ।अब तक तमाम राजरबार में अपना सिर पटक चुके हैं ।मगर जिम्मेदार दिल्ली का सत्ताधारी पक्ष इन बेकसूरों से कडी मेहनत और ड्यूटी का मेहनताना तक नहीं दे पाया है। उल्लेखनीय है कि रविवार को पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर एक बडी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई थी। इस ओपीएस के नाम पर तमाम राजनीतिक दलों के बडे-बडे नेता इनकी झंडाबरदारी करते दिखाई दिए। वजह साफ है 2024 के चुनाव के मद्देनजर सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने की बडी तैयारी है।

अब सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार के मातहत डीटीसी से रिटायर्ड बुजुर्ग पेंशनर्स और मार्शलों को उनका हक दिलवाने के लिए अब तक ये कथित ओपीएस की रैली में मौजूद कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को डीटीसी के बुजुर्ग पेंशनर्स और मार्शलों को चार महीनें से रोकी जा रही पेंशन और सैलरी पर इनका दुख और चीखें क्यों नहीं सुनाई दी है। आखिर इनकी लडाई कौन लडेगा?

राजनीतिक के कर्णधारों को डीटीसी के बुजुर्ग - पेंशनर्स , और मार्शलों की सैलरी की सिसकिंया क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं। वोट की राजनीति का खेला खेलते कथित रहनुमाओ को आखिर इन बुजुर्ग डीटीसी पेंशनर्स और मार्शलों के अलावा लाखों कांट्रेक्ट कर्मचारियों की ढलती जवानियों और हक की आवाज की सुद कब आएगी? यह तो वक्त ही। बताएगा। बहरहाल , डीटीसी के बुजुर्ग पेंशनर्स, और मार्शलों के साथ ही तमाम महकमें के दुखी कांट्रेक्ट कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने को तैयार है। इससे पहले ही कर्णधारों को उनकी मांगों पर अपना निर्णय लेना जरूरी है। वर्ना बागावती तेवर कभी भी सडकों से उठकर कथित कर्णधारों के शीशमहलों की तरफ रूख ना कर लें।

कर्नाटक में पुराने वाहनों पर कसेगा शिकंजा, जल्द खुलेगी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा

कर्नाटक की पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी) (आरवीएसएफ) देवनहल्ली में लगाई जाएगी। देश में 60 से ज्यादा आरवीएसएफ हैं, यह राज्य में पहला होगा। आने वाले दिनों में, सभी सरकारी वाहन जो 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते हैं, उन्हें आरवीएसएफ में स्क्रैप कर दिया जाएगा। कर्नाटक की पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी) (आरवीएसएफ) देवनहल्ली में लगाई जाएगी। देश में 60 से ज्यादा आरवीएसएफ हैं, यह राज्य में पहला होगा। आने वाले दिनों में, सभी सरकारी वाहन जो 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते हैं, उन्हें आरवीएसएफ में स्क्रैप कर दिया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग ने महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड को स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जहां जनता स्वैच्छिक आधार पर पुराने अनफिट वाहनों को स्क्रैप कर सकती है।

हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर हादसा: टूरिस्ट बस ने ट्रैक्टर ट्राली में मारी टक्कर , पिता और बेटे की दर्दनाक मौत

रुड़की की ओर से मनसब और अदनान ट्रैक्टर ट्राली में चेरी लेकर ज्वालापुर की ओर आ रहे थे। उनके ट्रैक्टर के पीछे पश्चिम बंगाल की एक टूरिस्ट बस भी तेज रफ्तार से आ रही थी। अचानक बस ने उसमें टक्कर मार दी।

नई दिल्ली। हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। ज्वालापुर में टूरिस्ट बस ने एक ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रैक्टर ट्राली पलटने से पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है साथ ही बस को कब्जे में ले लिया।

पुलिस के अनुसार, सुबह करीब पांच बजे रुड़की की ओर से मनसब (50) पुत्र महबूब और अदनान (19) पुत्र मनसब निवासी इब्राहिमपुर ट्रैक्टर ट्राली में चेरी लेकर ज्वालापुर की ओर आ रहे थे। उनके ट्रैक्टर के पीछे पश्चिम बंगाल की एक टूरिस्ट बस भी तेज रफ्तार से आ रही थी। जुर्स कंट्री के पास पहुंचते ही बस ने पीछे से ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्राली तुरंत पलट गई और उसमें सवार पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। लेकिन अस्पताल जाने तक दोनों दम तोड़ चुके थे।

ज्वालापुर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष सेमवाल ने बताया कि बस और ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है।

दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, बस करना होगा एक काम

आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बार 170000 ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 30 जून 2023 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा। इसमें भुगतान अयोग्य (नॉन कंपाउंडेबल) चालान और ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो कोर्ट में भेजा जा चुका हो।

नईदिल्ली। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो उसे भरने का एक अच्छा मौका है। दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक बार फिर लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप चालान का निपटान करा सकते हैं।

आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बार 1,70,000 ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

द्वारका, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, तीस हजारी, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में कुल 170 लोक अदालत लगेंगी और हर बेंच एक के पास 1000 चालान या नोटिस लिए भेजे जाएंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर इसका पूरा खाका तैयार किया है। दोनों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अपलोड कर दी है। लोक अदालत में सिर्फ भुगतान योग्य (कंपाउंडेबल) चालान ही लिए जाते हैं।

इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 30 जून 2023 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा। इसमें भुगतान अयोग्य (नॉन कंपाउंडेबल) चालान और ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो कोर्ट में भेजा जा चुका हो, वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका हो, जिसका भुगतान हो चुका है, या कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया हो। वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर विवादित चालानों को भी इससे बाहर रखा गया है।

कैसे कर सकते हैं चालान का निपटान?

नोटिस/चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगऑन करना होगा।

कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट लेने या डाउनलोड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उपरोक्त लिंक 4 oct को सुबह 10 बजे खुलेगा और नोटिस/चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा।

पर्ची डाउनलोड करने में सफल होने के बाद भी कुछ सतर्कता बरतनी होगी। चालान के निपटारे के लिए पर्ची में लिखे कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर में तय समय पर ही जाएं। साथ में अपना प्रिंट-आउट जरूर रखें।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/ 25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारत में कैंसर से महिलाओं को मौत का खतरा ज्यादा

लैंसेट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जल्द करें 5 काम, बच सकेगी जान

लैंसेट की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भले ही पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन कैंसर होने पर महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है. इसकी वजह सही समय पर कैंसर का पता न लगना और इलाज की कमी है. आज आपको बताएंगे कि महिलाएं किन तरीकों से कैंसर का वक्त रहते पता लगा सकती हैं.

भारत में कैंसर से पीड़ित अधिकतर महिलाओं को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है. इसका खुलासा लैंसेट कमीशन की नई रिपोर्ट में हुआ है. इसके अनुसार भारतीय महिलाओं में कैंसर के कारण होने वाली लगभग 63% मौतों को स्क्रीनिंग और निदान के जरिए रोका जा सकता था. जबकि 37% मौतों को समय पर सही इलाज से रोका जा सकता था. देश में कैंसर देखभाल में लैंगिक असमानता (gender inequity) पर लैंसेट आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. इसमें कहा गया है कि भले ही पुरुषों में कैंसर का खतरा अधिक होता है, लेकिन महिलाओं में कैंसर के मामले और मृत्यु दर ज्यादा रहती है.

नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली लगभग 69 लाख मौतें रोकी जा सकती थीं और 40.3 लाख महिलाओं का इलाज किया जा सकता था. वैश्विक स्तर पर कैंसर के नए मामलों में 48% महिलाएं होती हैं और कैंसर से होने वाली मौतों में 44% महिलाएं शामिल हैं. ऐसा तब होता है, जब महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर व सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है और उसे इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है. चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाएं जानकारी के अभाव, फाइनेंशियल पावर और प्राइमरी सर्विसेज की उपलब्धता की कमी के कारण सही समय पर और उचित इलाज नहीं करवा पाती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चाहे महिलाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहती हों और समाज के किसी भी तबके से आती हों, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जानकारी और निर्णय लेने की शक्ति की कमी होने की संभावना अधिक होती है.

नसों से बैड कोलेस्ट्रॉल निकाल देंगे ये 6 फूड आगे देखें...

इस बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट ?

नई दिल्ली एम्स के ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक शंकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कैंसर देखभाल में निश्चित रूप से जेंडर एक बड़ा फैक्टर होता है. गरीब महिलाओं को इस बारे में हेल्थकेयर को लेकर काफी कम जानकारी है. इसका असर महिलाओं पर पड़ता है. धूम्रपान और तंबाकू के संपर्क में आने वाले महिला और पुरुष दोनों को कुछ कैंसर का खतरा बराबर होता है, लेकिन महिलाओं का इलाज प्राथमिकता नहीं है. यही कारण है कि उनकी कंडीशन बदतर हो जाती है. कैंसर और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी के अलावा, सामाजिक बदलाव की भी जरूरत है. महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर है. इन कैंसर को इलाज के जरिए रोका जा सकता है. हालांकि महिलाएं इन समस्याओं को लेकर पुरुष डॉक्टरों के पास जाने से झिझकती हैं या महिला डॉक्टर से प्राइवेट पार्ट की जांच करने से भी हिचकिचाती हैं, जिससे इलाज में देरी होती है.

महिलाएं करें 5 काम, कैंसर की होगी रोकथाम

– सभी महिलाओं को हर महीने अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करनी चाहिए और साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए.

– 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए साल में एक बार मैमोग्राफी (mammography) करवानी चाहिए.

– जिन महिलाओं को सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान ब्रेस्ट में किसी गांठ का पता चलता है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करा चाहिए.

– सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए 25 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं को पैप स्मीयर परीक्षण (pap smear test) करवाना चाहिए. – महिलाओं को मानव पैपिलोमा वायरस का पता लगाने के लिए हर 5 या 10 साल में एचपीवी परीक्षण (HPV test) करवाना चाहिए।

अनियमित पीरियड्स से हैं परेशान? इन 3 चीजों से बने आयुर्वेदिक चूर्ण का करें 12 सप्ताह तक सेवन, दूर होगी कई परेशानी

यदि आपका पीरियड्स बार-बार मिस हो रहा है या फिर ब्लीडिंग कम होती है, पेट में बहुत दर्द रहता है तो आप मेथी, अलसी के बीज और काले तिल से बने चूर्ण का सेवन करें. यह मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के साथ ही वेट लॉस, स्ट्रेस कम करने, नींद अच्छी लाने में भी कारगर है.

अक्सर कुछ महिलाओं को पीरियड्स सही समय पर नहीं आता है. इर्रेगुलर पीरियड्स या डिले पीरियड्स की समस्या से अधिकतर महिलाएं परेशान रहती हैं. यह समस्या बढ़ती उम्र में अधिक देखने को मिलता है. कई बार पीसीओडी और पीसीओएस से ग्रस्त महिलाओं में भी अनियमित मासिक धर्म की समस्या देखी जाती है. कुछ महिलाओं को पीरियड्स तो होता है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होती है. ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है और दो दिन के अंदर ही पीरियड्स खत्म भी हो जाता है. इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ महिलाएं या लड़कियां दवाओं का सेवन करती हैं. कई बार हॉर्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीरियड्स अनियमित हो जाता है. हॉर्मोनल पिल्स के सेवन से शारीरिक और मानसिक रूप से नकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए पिल्स की बजाय नेचुरल चीजों का सेवन करना चाहिए. इनसे वजन भी नहीं बढ़ता है. महिलाओं में होने वाली मूड स्विंग, डिप्रेशन, इन्सोम्निया की समस्या भी नहीं होती है.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. दीक्षा भावसार (Dr. Dixa Bhavsar) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने डिले और इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या को दूर करने का नेचुरल घरेलू नुस्खे के बारे में बताया है. उन्होंने एक चूर्ण के बारे में बताया है, जो पीरियड्स संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है. ये चूर्ण अलसी के बीज, मेथी के दाने और काली तिल को एक साथ पीसकर तैयार किया गया है.

अनियमित पीरियड्स की समस्या दूर करेगा ये नेचुरल उपाय

आपको भी इर्रेगुलर पीरियड्स, डिले पीरियड्स या फिर मासिक धर्म के दौरान कम ब्लीडिंग होने की समस्या है तो आप इस पाउडर का सेवन जरूर करें. इसके लिए आप रोस्ट की हुई काली तिल, मेथी के बीज और अलसी के बीज बराबर मात्रा में लें. इसे मिक्सी में डालकर पाउडर की तरह पीस लें. इसे सुबह के समय या फिर रात में सोने से पहले 1 छोटा चम्मच गर्म पानी के साथ खाएं. इसे आप प्रतिदिन लगभग 12 सप्ताह यानी तीन महीने तक सेवन करें. आप इस चूर्ण का सेवन प्रत्येक महीने पीरियड्स होने के दूसरे दिन से लेकर आखिरी दिन तक कर सकती हैं. पीरियड्स समाप्त होते ही फिर से इसे खाना शुरू कर सकती हैं.

मेथी, अलसी, काले तिल से बना चूर्ण कैसे है फायदेमंद

मेथी, अलसी के बीज और काले तिल से तैयार ये पाउडर पीरियड्स संबंधित कई समस्या को दूर करता है. पेट में दर्द, ऐंठन, क्रैम्प, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, स्ट्रेस, रेगुलर पीरियड्स साइकिल, अच्छी नींद लेने में बेहद कारगर है. काली तिल पीरियड्स को रेगुलर बनाने के साथ ही पीरियड्स के दर्द को भी दूर करता है. मेथी के बीज फाइटोएस्ट्रोजेन्स से भरपूर होते हैं, जिसका एस्ट्रोजेन लेवल पर पॉजिटिव एफेक्ट पड़ता है. ये पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो को सुधारता है. साथ ही इसके सेवन से वजन कम होता है, शुगल लेवल भी बढ़ने नहीं देता है.

'फंगल संक्रमण' के कारण क्या हैं?

फंगल इंफेक्शन से पीड़ित लोगों की संख्या भी कम नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला यह फंगल संक्रमण आपको एक समय के बाद पूरी तरह सदमे में डाल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? किस बात का ध्यान रखा जा सकता है? आइए आज इसी के बारे में जानते हैं...

कारण क्या हैं?:

गर्म और आर्द्र वातावरण इस समस्या का कारण बनता है।

जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है उनमें फंगल संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है।

गीले कपड़े पहनना।

तंग जूते या कपड़े पहनना।

लंबे समय तक मोज़े पहने रहना।

व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान न रखना।

एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव

कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली

1. कैंडिडा अल्बिकन्स : यह एक फंगल संक्रमण है जो जननांगों के पास मुंह के पास की त्वचा, नम त्वचा पर होता है।

2. दाद : यह भी एक फंगल संक्रमण है। जो मुख्य रूप से त्वचा, खोपड़ी, पैरों, जांघों और जननांगों के पास होता है।

किस बात का ध्यान रखें?:

व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें।

बाथरूम या सार्वजनिक स्नान क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें।

हर समय एक जैसे मोज़े न पहनें।

ज्यादा टाइट जूते न पहनें।

किसी का सामान प्रयोग न करें।

प्रभावित क्षेत्र पर दिन में 3-4 बार 2.5 PH के अम्लीय पानी का छिड़काव करना चाहिए।

गांधी जयंती व शास्त्री जयंती पर स्वच्छता अभियान प्रारम्भ

नई दिल्ली। गन्तव्य संस्थान, भारतीय प्राकृतिक चिकित्सक संघ, सर्वधर्म वेलफेयर सोसायटी,अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद एवं रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में 2 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9 बजे स्वच्छता अभियान के तहत सफाई का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर बच्चों के साथ-साथ बड़ों ने भी इलाके में सफाई की और गांधी जी व शास्त्री जी के चित्र पर दीपक जलाकर कर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में सभी बच्चों को सर्टिफिकेट व पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया ।

इस अवसर पर डॉ अरविन्द कुमार त्यागी अध्यक्ष, अर्चना त्यागी डायरेक्टर गन्तव्य संस्थान डॉ प्रबोध चन्दोल महासचिव व डॉ हीरालाल मीणा भारतीय प्राकृतिक चिकित्सक संघ डॉ राजेंद्र रावत अध्यक्ष व विजय शर्मा कोषाध्यक्ष रेजिडेंशियल वेल्फेयर सोसायटी, अचिन शर्मा सुपरिटेंडेंट आखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद सहित सर्वश्री टीकाराम, ब्रह्मप्रकाश, मुनिन्द्रा त्यागी, संगीता व विमलेश के साथ-साथ सलोनी व लिपिका के नेतृत्व में बच्चों ने भी भाग लिया। डॉ प्रबोध व अर्चना त्यागी ने बच्चों को गांधी व शास्त्री जी के बारे में बताया और सफाई बनाए रखने की प्रतिज्ञा दिलाई गई।

गांधी जयन्ति पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रमिकों ने किया याद

अनूप कुमार शर्मा , भीलवाड़ा । भीलवाड़ा जिला इंटक की कार्यकारिणी की बैठक गांधी मजदूर सेवालय में बार काउंसिल इंडिया के को चेयरमैन सुरेशचंद्र श्रीमाली के आतिथ्य एंव दीपक व्यास की अध्यक्षता में हुई, जिसमे महात्मा गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके द्वारा 3 मई 1947 को इंटक की स्थापना की गई।जिससे आजाद देश में उद्योग एवं श्रमिक हितों की लगातार रक्षा हो सके, उनकी इसी सोच को नमन करते हुए संगठन इंटक लगातार श्रमिक हितों के लिए संघर्षशील रही है एवं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीयों ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए श्रमिक हितों में सदैव संघर्ष करने के लिए आह्वान किया इस अवसर पर भीलवाड़ा के पुरुषोत्तमदत्त शर्मा, ।टटछस् अध्यक्ष, अविचल व्यास, कुणाल ओझा, ईश्वर खोईवाल, पश्चिम ब्लाक अध्यक्ष मंजु पोखरणा, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जैन, गुणवंत जैन, विरेन्द्र जैन, मंजु राठौड़, प्रीति शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला इंटक, कान सिंह जिला महामंत्री, राजकुमार जोशी, ओम वैष्णव, मेवाराम खोईवाल, नंदलाल गाडरी रामेश्वर खटीक, राधेश्याम शर्मा, डूंगर सिंह, भैरू लाल पारीक, जहीरूदीन मेवाफरोश उपस्थिति थे, आभार कान सिंह ने व्यक्त किया व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

हजारों मरीजों को राहत: सफदरजंग में काफी कुछ बदल जाएगा, ओपीडी से लेकर जांच रिपोर्ट तक; पढ़ें खास रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

नए आदेश के तहत ओपीडी में इलाज के लिए शाम साढ़े पांच बजे तक पर्ची बनवा सकेंगे। शुरूआत में सर्जरी, बाल रोग और मेडिसिन विभाग के मरीजों को सुविधा मिलेगी। इसमें आगे विस्तार होगा।

नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल में उपचार करवाने आ रहे मरीजों को मंगलवार से देर शाम तक ओपीडी की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में अभी सुबह 11:30 बजे तक ओपीडी की पर्ची बनती है। इसके बाद आने वाले मरीजों को उपचार के लिए आपातकालीन सेवाओं में जाना पड़ता था, जिससे इमरजेंसी के मरीजों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए देर शाम तक ओपीडी चलाने का फैसला लिया गया है। नए आदेश के तहत ओपीडी में इलाज के लिए शाम साढ़े पांच बजे तक पर्ची बनवा सकेंगे। शुरूआत में सर्जरी, बाल रोग और मेडिसिन विभाग के मरीजों को सुविधा मिलेगी। इसमें आगे विस्तार होगा।

अस्पताल में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से रोजाना करीब नौ से 10 हजार मरीज उपचार करवाने आते हैं। उसी दिन उपचार न मिलने पर इन्हें रातभर अस्पताल परिसर में ही रहना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए पुराने कोविड सेंटर में सुविधा शुरू की गई है। इस केंद्र पर दोपहर बाद से पर्ची बनने लगेगी।

एम्स की तर्ज पर ऑनलाइन रिपोर्ट

सफदरजंग अस्पताल भी एम्स की तर्ज पर रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन देने की दिशा में काम कर रहा है। अस्पताल प्रशासन की कोशिश है कि पूरे परिसर को हाईटेक वाईफाई सिस्टम से जोड़ा जाए और उसके बाद पूरी सुविधा को ऑनलाइन किया जाए। इससे मरीजों को रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं होगा। डॉक्टर भी रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा लैब की सुविधा का सेंट्रलाइज्ड भी किया जाएगा। इससे मरीजों को सैंपल देने के लिए अलग-अलग जाने की जरूरत नहीं होगी।

शुरू होगी प्राइवेट ओपीडी

अस्पताल में जल्द ही प्राइवेट ओपीडी भी शुरू होगी। फिलहाल यह कैसे काम करेगा, इसे लेकर रूप रेखा तैयार की जा रही है। हो सकता है यह निजी अस्पताल की तरह ही सेवाएं दें। इससे पहले अस्पताल ने प्राइवेट वार्ड की भी सुविधा शुरू की थी जिसमें शुल्क देकर मरीज अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उपचार करवा सकता है।

बेहतर सुविधाओं के साथ जनवरी में शुरू होगा एसआईसी

सफदरजंग अस्पताल का नया स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर

आधुनिक सुविधाओं के साथ जनवरी तक शुरू हो गया है। इसके नए भवन में जांच से लेकर अन्य सभी सुविधाओं को एकीकृत किया जा रहा है। ताकि मरीजों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेंटर का उद्घाटन कर सकते हैं। नए भवन में शिफ्ट होने के बाद पुराने भवन में सेंट्रलाइज्ड लैब को तैयार किया जाएगा।

डॉग बाइट क्लीनिक का होगा विस्तार

सफदरजंग अस्पताल में डॉग बाइट क्लीनिक का विस्तार होगा। अभी यह क्लीनिक इमरजेंसी के बेसमेंट में चल रही है। यहां मरीजों को पहली डोज दी जाती है, दूसरी डोज के लिए ओपीडी में आना पड़ता है। यहां रोजाना 250 से 300 मरीजों को वैक्सीन दी जा रही है। आने वाले दिनों में इस क्लीनिक के विस्तार को लेकर काम चल रहा है।

बनेगा मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक

अस्पताल में एम्स की तर्ज पर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बनेगा। इसे लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। यह सुविधा विकसित होने के बाद अस्पताल में डिलीवरी करवाने आ रही हजारों महिलाओं को सुविधा होगी। इसके अलावा लड़कों के लिए छात्रावास और ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा।

ऑनलाइन रेफर सिस्टम

दूसरे अस्पताल से रेफर होकर आने वाले मरीजों के लिए सफदरजंग अस्पताल भी ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में विचार कर रहा है। इसके तहत अस्पताल आने से पहले ही मरीज की जानकारी अस्पताल के पास होगी। ऐसा होने से वेंटिलेटर सहित अन्य की व्यवस्था पहले से की जा सकेगी। साथ ही दूसरे अस्पतालों से भी संपर्क साधा जा सकेगा।

एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम को जारी किया नोटिस

पार्क में लगाए मोबाइल टावर को लेकर देना होगा जवाब

सरिता विहार के पॉकेट-ए स्थित पार्क में लगाए गए मोबाइल टावर के विरुद्ध जन कल्याण समिति द्वारा भेजी भेजी गई लेटर-पिटीशन का संज्ञान लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से आठ सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यह भी कहा कि जिस मोबाइल कंपनी ने टावर लगाया है उसका भी रिपोर्ट में जिक्र किया जाए।

नई दिल्ली। सरिता विहार के पॉकेट-ए स्थित पार्क में लगाए गए मोबाइल टावर के विरुद्ध जन कल्याण समिति द्वारा भेजी भेजी गई लेटर-पिटीशन का संज्ञान लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से रिपोर्ट मांगी है।

एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आवेदन में उठाए गए मुद्दा अहम है। एनजीटी ने एमसीडी आयुक्त को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि जिस मोबाइल कंपनी ने टावर लगाया है उसका भी रिपोर्ट में जिक्र किया जाए।

स्वास्थ्य के लिए खतरा है टावर: शिकायतकर्ता

आवेदनकर्ता जन कल्याण समिति ने पत्र में कहा कि पार्क में लगाया गया मोबाइल टावर वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह भी कहा कि पार्क में टावर लगाए जाने के कारण बच्चे पार्क में खेलने से वंचित हो गए हैं।

वहीं, स्थानीय नागरिक व वरिष्ठ नागरिक भी व्यायाम समेत अन्य विभिन्न कार्यों के लिए पार्क का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

वीकेंड पर घूमने गए दिल्ली के युवक की ऋषिकेश में मौत, चप्पल निकालते समय तेज बहाव में बहा

परिवहन विशेष न्यूज

सप्ताहांत (वीकेंड) पर अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया दिल्ली के जनकपुरी का रहने वाला एक युवक गंगा में डूब गया। एसडीआरएफ की टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया। ऋषिकेश के जागरण संवाददाता के अनुसार थाना प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती रितेश शाह ने बताया कि शिवम सिंह(24) पुत्र मंजय सिंह निवासी मकान नंबर बी-137 जनकपुरी अपने दो दोस्तों के साथ घूमने आया था।

दिल्ली। सप्ताहांत (वीकेंड) पर अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया दिल्ली के जनकपुरी का रहने वाला एक युवक गंगा में डूब गया। एसडीआरएफ की टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया। ऋषिकेश के जागरण संवाददाता के अनुसार, थाना प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती रितेश शाह ने बताया कि शिवम सिंह(24) पुत्र मंजय सिंह निवासी मकान नंबर बी-137 जनकपुरी अपने दो दोस्तों के साथ घूमने आया था। सोमवार की दोपहर इन सभी ने राफ्टिंग की।

पैर फिसलने से तेज बहाव में बहा

नीम बीच के समीप राफ्टिंग समाप्त होने के बाद तीनों गंगा किनारे बैठे थे। इस बीच एक दोस्त की चप्पल पानी में बह गई। चप्पल लेने के लिए शिवम पानी में गया और पैर फिसलने से तेज बहाव में लापता हो गया। एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में 15 मीटर गहराई से शव को बरामद किया।

मामूली विवाद में लड़के की चाकू मारकर हत्या

एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा

दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में एक लड़के की हत्या को मामले में पुलिस ने सुलझा दिया है। लड़के की चाकू मारकर हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक के साथ सके साथ चार लोगों ने झगड़ा किया और उसके बाद आकाश पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

नई दिल्ली। दक्षिण पूर्व दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में एक लड़के की हत्या को मामले में पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी के रहने वाले अनुराग पालीवाल उर्फ निक्की (30) के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार, एक अक्टूबर 2023 को एक लड़के को चाकू मारने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल आकाश को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था। बाद में वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शिकात के मुताबिक उसके साथ चार लोगों ने झगड़ा किया और उसके बाद आकाश पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में धारा 302/34 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की आगे की जांच शुरू की गई।

साकेत में मॉल के पास चल रही अवैध गतिविधि, कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी के एक मॉल के पास एक पार्किंग माफिया द्वारा ओवरचार्जिंग और जबरन वसूली सहित कथित अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पार्किंग माफिया ने मॉल के पीछे सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और लोगों से अवैध पार्किंग शुल्क के रूप में जबरन रुपये की वसूली कर रहे थे।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी के एक मॉल के पास एक पार्किंग माफिया द्वारा ओवरचार्जिंग और जबरन वसूली सहित कथित अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट साकेत मॉल के पास कथित पार्किंग माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट में दाखिल आवेदन के अनुसार, पार्किंग माफिया ने मॉल के पीछे सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और लोगों से अवैध पार्किंग शुल्क के रूप में जबरन रुपये की वसूली कर रहे थे। पुलिस रिपोर्टों पर गौर करते हुए, अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) और संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने पुष्टि की है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा आवंटित पार्किंग स्थल पर ओवरचार्जिंग हुई थी।

शादी न करने पर की थी मोनिका की हत्या, दो साल बाद मिले कंकाल से खुलेंगे राज

दिल्ली पुलिस की पूर्व महिला सिपाही मोनिका की हत्या के राज अब जल्द खुलेंगे। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वह भी मोनिका का सहकर्मी थी। आरोपी युवती पर शादी के लिए दवाब बना रहा था जिसका वह विरोध कर रही थी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को नाले में फेंक दिया था और उसके ऊपर पत्थर बांध दिया था।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की पूर्व महिला सिपाही मोनिका की हत्या के राज अब जल्द खुलेंगे। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वह भी मोनिका का सहकर्मी थी। आरोपी युवती पर शादी के लिए दवाब बना रहा था, जिसका वह विरोध कर रही थी और उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद उसने शव को नाले में फेंक दिया था और उसके ऊपर पत्थर बांध दिया था। जिससे शव नाले में ही डूबा रहे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद कर लिया है। कंकाल का मिलान मोनिका के स्वजनों के डीएनए से किया जाएगा।

कंकाल पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

यह पूरी घटना दो वर्ष पहले सितंबर, 2021 में हुई थी। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, जिससे यह पता चल पाएगा कि आरोपी ने महिला को किस तरह मारा था। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। उसकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

2018 में हुई थी मुलाकात

वर्ष 2018 में पीसीआर यूनिट में नौकरी के दौरान सुरेंद्र और मोनिका की मुलाकात हुई थी। दोस्ती हुई और फिर प्रेम करने लगे। हवलदार ने मोनिका से अविवाहित होने का झूठ बोला था। हवलदार ने शादी करने के लिए मोनिका पर दवाब बना रहा था, लेकिन वह राजी नहीं थी। जिस पर हवलदार ने सितंबर 2021 में मोनिका को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसके शव में पत्थर बांधकर बुराड़ी पुश्ता के पास नाले में डुबा दिया गया।

विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच रवींद्र सिंह यादव के मुताबिक गिरफ्तार हवलदार सुरेंद्र सिंह अलीपुर का रहने वाला है। वर्तमान में उसकी तैनाती पीसीआर यूनिट में है। वर्ष 2012 में वह बतौर ड्राइवर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था।

अपराध में सुरेंद्र की उसके बहनोई ने भी की मदद

हत्या के बाद अपराध को छिपाने के लिए हवलदार की मदद करने वाले बहनोई रविन और फर्जी दस्तावेजों पर सिमकार्ड मुहैया कराने वाले डीलर राजपाल को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।

बहनोई स्वजनों को फोन करके करता था गुमराह

हवलदार सुरेंद्र सिंह अपने बहनोई रविन के जरिये मोनिका के बुलंदशहर निवासी स्वजन को फोन करवाकर दिलासा देता रहा कि वह अपनी मर्जी से गई है। पुरुष मित्र के साथ खुशी से रह रही है। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। इधर, खुद सुरेंद्र केस की तफ्तीश की जानकारी करने के लिए मोनिका के स्वजन के साथ तो कभी अकले मुखर्जी नगर थाने जाता रहा, ताकि पुलिस उस पर शक न करे।

यूपी गेट पर जुटे किसानों ने किया हवन, दिल्ली में प्रवेश की कोशिश हुई फेल; किया गया डायवर्जन

गाजियाबाद स्थित दिल्ली के बार्डर पर महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यूपी गेट पर बड़ी संख्या में किसान जुटे। किसानों ने यूपी गेट पर हवन किया फिर दिल्ली की ओर कुच किया। किसानों को हवन के मद्देजनर पुलिस ने मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की थी।किसान पिछले चार साल से यूपी गेट पर महात्मा गांधी की जयंती पर यूपी गेट पर हवन करते हैं।

साहिबाबाद। गाजियाबाद स्थित दिल्ली के बार्डर पर महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यूपी गेट पर बड़ी संख्या में किसान जुटे। किसानों ने यूपी गेट पर हवन किया, फिर दिल्ली की ओर कुच किया। किसानों को हवन के मद्देजनर पुलिस ने मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की थी।

भारी सुरक्षा बल के बीच हुआ हवन

बता दें कि किसान पिछले चार साल से यूपी गेट पर महात्मा गांधी की जयंती पर यूपी गेट पर हवन करते हैं। सोमवार सुबह 9 बजे से यूपी गेट पर किसान जुटने शुरू हो गए। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां पहले से ही पुलिसकर्मियों की तैनात की गई थी।

पुलिस ने डायवर्ट किया यातायात

वहीं, यातायात पुलिस ने लिंक रोड से यूपी गेट की ओर आने वाले वाहनों को डॉ. बर्मन रोड की ओर डायवर्ट कर दिया गया। यूपी गेट से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस में भी यूपी गेट पर बैरिकेडिंग की हुई थी।

यूपी गेट पर हवन के बाद किसानों ने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।इसके बाद किसान फिर से यूपी गेट पर जमा हो गए। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम भी तैनात है।

आगे भी करते रहेंगे हवन: किसान नेता

किसानों का कहना है कि यूपी गेट पर उन्होंने एक साल से अधिक समय तक धरना दिया है। साल 2018 में उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया था। जिस वजह से वह यहां पर हर साल महात्मा गांधी की जंयती पर हवन करते हैं। आगे भी वह हवन करते रहेंगे।

गाजियाबाद में गाड़ी पर लगा रखा था धार्मिक स्टीकर, चालान कटने पर हुआ बवाल

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में वाहन पर धार्मिक स्टीकर लगाने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया तो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दे दिया। पुलिस ने उन्होंने समझाकर शांत कराकर सड़क से हटाया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी भैया ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि पुलिस ने शीशे पर लगे धार्मिक स्टीकर लिखवाने पर एक कैंटर चालक का चालान काट दिया है। दल के कार्यकर्ता राजनगर एक्सटेंशन स्थित मोरटी मोड़ पर पहुंचे और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से कार्रवाई के संबंध में लिखित आदेश दिखाने को कहा। पुलिसकर्मी लिखित में आदेश नहीं दिखा पाए तो कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दे दिया।

12वीं की छात्रा का फंदे से लटका मिला शव, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट

गाजियाबाद के पुराना विजय नगर में सोमवार तड़के करीब तीन बजे 12वीं की छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला। निशांत के मुताबिक घर में कोई परेशानी नहीं थी। न ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा कदम उठाएगी। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। शुरुआती जांच में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है।

गाजियाबाद। पुराना विजय नगर में सोमवार तड़के करीब तीन बजे 12वीं की छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला। एसीपी कोतवाली निमिष पाटील ने बताया कि शुरुआती जांच में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है।

JEE की कर रही थी तैयारी

हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। निशांत ने बताया कि उनकी बहन लक्षिता 12वीं में पढ़ने के साथ ही आईआईटी जेईई की तैयारी कर रही थी। रविवार रात वह उन्हीं के कमरे में पढ़ रही थी। साढ़े 11 बजे बोली, भैया मैं जा रही हूं।

मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट

फोन चार्जिंग पर लगा देना। रात को ढाई बजे उठीं तो लक्षिता उनके पास नहीं थी। वह बाहर आईं और लाइट जलाई तो दूसरे कमरे में लक्षिता का शव फंदे पर लटका था। शोर सुनकर वह व अन्य लोग उठे, तुरंत पुलिस को सूचना दी। निशांत के मुताबिक घर में कोई परेशानी नहीं थी। न ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा कदम उठाएगी। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है।

सड़क पार करते समय ई-रिक्शा में कार ने मारी टक्कर, किशोरी की मौत

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। कविनगर क्षेत्र में हापुड़ चुंगी पर रेड लाइट होने के बाद ई-रिक्शा जेब्रा क्रॉसिंग से आगे हो गया। इतने में स्वदेशी मार्ग की ओर से आई कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा पलट गई और उसमें सवार 15 साल की फिजा की मौत हो गई जबकि उसकी मां व अन्य भाई-बहन घायल हो गए। मौके से कार चालक फरार हो गया। मामले में फिजा की मां अफसाना ने कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुरादनगर के मलिक नगर की रहने वाली अफसाना का कहना है कि वह बच्चों के साथ ई-रिक्शा से पुराना बस अड्डा से मसूरी की जा रही थीं। हापुड़ चुंगी पर अचानक तेज रफ्तार कार ने आकर ई-रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा पलट गई और उनकी बेटी की मौत हो गई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी व अन्य लोगों ने उन्हें बाहर निकाला इतने में कार चालक फरार हो गया। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

होटल की बुकिंग के नाम पर की 6.44 लाख की धोखाधड़ी

गाजियाबाद। कविनगर क्षेत्र के रहने वाले युवक को शातिर ने जाल में फंसाकर उनके क्रेडिट कार्ड से 6.44 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। शातिर ने होटल की बुकिंग के नाम पर ठगी की। मामले में उन्होंने साइबर सेल में शिकायत कर कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। युवक का कहना है कि 24 सितंबर को उनके पास एक कॉल आई। कॉलर ने होटल की बुकिंग करने के लिए उनके कार्ड की डिटेल मांगी। इसके बाद शातिर ने उनके दो कार्ड से छह बार में 6.44 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन कर ली। मोबाइल पर मेसेज आने पर उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। एसीपी कविनगर का कहना है कि मामले में साइबर सेल की मदद लेकर जांच कराई जा रही है।

332 घरों में मिला मच्छरों का लार्वा दो डेंगू मरीजों की पुष्टि

गुरुग्राम। रविवार को दो नए मरीज मिलने के साथ ही अब तक जिले में 199 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। नागरिक अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। जिले के संवेदनशील इलाके वजीराबाद में भी मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार तक यहां डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 50 के पार हो गया। पटौदी क्षेत्र में जिले के सबसे कम चार मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को पूरे जिले में 55 लोगों की जांच के लिए स्लाइड बनाई गई। डेंगू के लार्वा की तलाश के लिए रविवार को 6635 घरों की जांच की गई। इसमें से 332 घरों में लार्वा मिला। ऐसे लोगों को लापरवाही बरतने के कारण विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उधर, अस्पताल में उपचाराधीन 34 डेंगू मरीजों में से कुछ की हालत अस्थिर है। इन मरीजों की हालत पर विभाग लगातार नजर रख रहा है। इधर, रविवार को छुट्टी होने के कारण जिला अस्पताल में केवल 13 लोग ही डेंगू की जांच के लिए पहुंचे। जिले में अब तक 6453 की जांच पर 199 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है।

जिला स्वास्थ्य विभाग के डेंगू एवं मलेरिया रोकथाम विभाग प्रभारी डॉ. जय प्रकाश ने बताया कि डेंगू को काबू करने के लिए जागरूकता अभियान पर पूरा जोर है। लोगों को बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं।

उपायुक्त निशांत यादव ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों की पालना की सुनिश्चित

अब आवश्यक सेवाओं के लिए ही चलेगा जनरेटर, बाकी सेवाओं पर लगी रोक

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। अक्तूबर की शुरुआत के साथ ही आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले में डीजल चालित जनरेटर्स के संचालन पर रोक लगा दी गई है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय व कार्यालय परिसरों में (बिजली आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में केवल पावर बैकअप के लिए) डीजी सेट के इस्तेमाल को लेकर नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। आपातकालीन व विशेष सेवाओं में डीजी सेट के इस्तेमाल पर 31 दिसंबर तक राहत का प्रावधान किया गया है।

जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि पूर्व में विभिन्न हितधारकों की ओर से दिए गए तर्कों और प्रस्तुतियों, जमीनी स्तर के कार्यान्वयन में मुद्दों, आरईसीडी की उपलब्धता, दोहरी ईंधन प्रणालियों, सीपीसीबी-फोर मानकों के लिए नए जेनसेट की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके बाद सीएक्यूएम ने डीजी सेट संचालन के लिए एक अनुसूची को अपनाने का निर्देश दिया है। इस अनुसूची में वर्णित नियम एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे। यह नियम डीजी सेट की क्षमता, उपयोग के लिए विनियम व उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली के संदर्भ में होंगे।

स्वच्छ ईंधन वाले डीसी सेट चलेंगे

उपायुक्त यादव ने बताया कि एलपीजी, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, प्रोपेन व ब्यूटेन पर चलने वाले सभी क्षमताओं के डीजी सेट के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तीन नवंबर 2022 को जारी अधिसूचना में विभिन्न मानक निर्धारित किए हुए हैं। इसमें 800 किलोवाट तक की सभी क्षमताओं के बिजली उत्पादन सेट, 800 किलोवाट और उससे अधिक , 125 किलोवाट से 800 किलोवाट तक दोहरी ईंधन प्रणाली मोड व प्रमाणित वेंडर या एजेंसी द्वारा रेट्रोफिटेड ईसीडी के संचालन पर ग्रैप अवधि के दौरान भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।

इन सेवाओं के लिए रहेगी 31 दिसंबर तक छूट

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी ने बताया कि 31 दिसंबर तक राहत प्राप्त क्षेत्रों में डीसी सेट चल सकेगा। इसमें केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लिफ्ट, एस्केलेटर के संचालन में डीजी सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह भी सुनिश्चित करना होगा इन स्थानों पर डीजी सेट का इस्तेमाल केवल लिफ्ट के संचालन तक ही सीमित हो। चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल, नर्सिंग होम व स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) जिनमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों, उपकरणों, दवाओं और दवाओं के निर्माण में शामिल इकाइयां शामिल हैं। रेलवे सेवाएं व रेलवे स्टेशन के लिए, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एमआरटीएस सेवाएं, ट्रेनों और स्टेशन सहित, हवाई अड्डे और अंतर- राज्य बस टर्मिनल (आईएसबीटी), सीवरेज शोधन संयंत्र, वाटर पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा व राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ दूरसंचार और आईटी/ डेटा सेवाओं के लिए इस अवधि में डीजी सेट के इस्तेमाल की छूट रहेगी। नवीनतम निर्देशों के तहत इस विषय में कानूनों, नियमों, विनियमों, निर्देशों आदि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई से बचना चाहिए।

ईवी चार्ज कर रहे हैं तो इन जरूरी टिप्स को अपनाएं, सुरक्षा के साथ बढ़ेगी बैटरी लाइफ भी

दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, इन बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा सावधानियां भी ईवी खरीदारों और मालिकों के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। इंटरनल कंब्शन इंजन (आईसीई) से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों में काफी कम मूविंग पार्टस होते हैं। हालांकि, चुनिंदा परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की संभावना विशेष रूप से होती है। साथ ही, ईवी में लगी आग की तीव्रता आईसीई वाहन में लगी आग की तुलना में बहुत ज्यादा होती है।

ईवी में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि वे बिजली से चलते हैं, और बैटरी पैक पावर जेनरेट करते समय अत्यधिक गर्मी भी पैदा करता है। इलेक्ट्रिक वाहन को सुरक्षित वातावरण में चार्ज करना चालक की सुरक्षा और वाहन के बैटरी पैक के स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को कहां चार्ज करते हैं, चाहे वह घर पर हो या सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन पर, कुछ एहतियाती सुझावों का पालन करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां हम आपको कुछ अहम टिप्स बता रहे हैं।

प्रमाणित चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करें

सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या से बचने के लिए हमेशा प्रमाणित चार्जर और प्रमाणित चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करें। प्रमाणित चार्जिंग स्टेशन और उनके चार्जर सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं और ओवरचार्जिंग और ओवरहीटिंग जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो कही और चार्ज करने पर आपके ईवी के लिए समस्या का कारण बन सकते हैं।

अत्यधिक तापमान में चार्ज करने से बचें

अत्यधिक तापमान आपके वाहन के बैटरी पैक के लिए हानिकारक हो सकता है और इसकी वजह से बैटरी की लाइफ भी कम हो सकता है। इसलिए, अत्यधिक तापमान में ईवी को चार्ज करने से बचने की हमेशा सलाह दी जाती है। ईवी को सीधी धूप में चार्ज करने से बचें, क्योंकि गर्मी का असर चार्जिंग सिस्टम और बैटरी पैक पर भी पड़ सकता है।

गीली स्थितियों में चार्ज करने से बचें

पानी के साथ बिजली का कोई मेल नहीं है, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा सुरक्षा पर जोखिम होता है। इसलिए, गीली परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ईवी को गीली स्थिति में चार्ज किया जाना है, तो हमेशा सुनिश्चित करें कि चार्जिंग स्टेशन और केबल पानी के संपर्क में न आएं।

ज्यादा चार्ज न करें

ओवरचार्जिंग किसी भी बैटरी के लिए खराब है, चाहे वह स्मार्टफोन की हो या इलेक्ट्रिक वाहन की। ओवरचार्जिंग से बैटरी खराब हो सकती है और उसकी लाइफ काफी कम हो सकता है। ज्यादातर आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए एक बिल्ट-इन मैकेनिज्म (अंतर्निर्मित तंत्र) के साथ आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वाहन की चार्जिंग प्रक्रिया पर नजर रखना महत्वपूर्ण होता है।

इस माह लॉन्च हो सकती है टाटा पंच इलेक्ट्रिक, सामने आई कीमत

पंच ईवी की शुरुआती कीमत 12 लाख रु हो सकती है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन निर्माता कंपनी, टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच जल्द इलेक्ट्रिक अवतार में आ सकती है। इसके कयास काफी पहले से लगाए जा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स इस माह एसयूवी पंच के इलेक्ट्रिक वैरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। बता दें कि, टाटा मोटर्स की ओर से पहले पुष्टि की गई थी कि वह इस साल के आखिर तक तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करेगी। हाल ही में कंपनी ने अपनी नेक्सन ईवी के फेस्लिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में उतारा है। इस एसयूवी में कई सारे बेहतरीन फीचर्स और अट्रैक्टिव एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन देखने को मिलती है। **आइए जानते हैं पंच ईवी (Punch EV) से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में...**

पंच ईवी में क्या होगा खास स्पाई तस्वीरों से चता चलता है कि, पंच ईवी हैरियर और सफारी जैसी एसयूवी से प्रेरित होगी। इसमें रीडिजाइन किया गया फ्रंट लुक देखने को मिल सकता है। इसमें वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलाइट सेटअप के साथ-साथ डिजिटल लोगो के साथ टाटा का नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल सकता है। क्या कहती है मीडिया रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि, Punch EV कंपनी की ओर से पेश किए जाने वाला अगला प्रोडक्ट होगा, जिसे अक्टूबर महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि, टाटा मोटर्स लंबे समय से पंच के इलेक्ट्रिक अवतार की टेस्टिंग कर रहा है और कई अलग-अलग मौकों पर इसे स्पॉट भी किया गया है। रिपोर्ट की मानें तो, Punch EV कंपनी के मौजूदा जिप्ट्रॉन पावरट्रेन पर बेस्ड होगी, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों में भी करती है। Tata Punch EV के फ्रंट में चार्जिंग सॉकेट दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फोर-व्हील डिस्क ब्रेक, नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। वहीं इंटीरियर की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का बड़ा ट्चस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ और दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है। इसके डिजाइन में सेंट्रोल कंसोल देखनेको मिल सकता है। टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज सेपता चलता है कि इसमें 360-डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। यह भी पढ़े -टेस्ला का इस साल भारत से 1.9 अरब डॉलर तक के ऑटोमोबाइल पार्ट्स मंगाने का लक्ष्य है : पीयूष गोयल संभावित कीमत लॉन्च से पहले Punch EV की संभावित कीमत सामने आई है। जिसके अनुसार, इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख रुपए हो सकती है, जो कि इसके एडवेंचर वैरिएंट की होगी। वहीं इसके टॉप वैरिएंट की कीमत 14.60 लाख रुपए तक जा सकती है। हालांकि, इसकी सही कीमतों की जानकारी लॉन्च के साथ ही मिल सकेगी।

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लगेंगे पंख, इस राज्य में मिला EV बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का बड़ा खजाना

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है तो इससे इलेक्ट्रिक बैटरियां सस्ती होंगी और अंततः इलेक्ट्रिक कारों की कीमत भी कम हो सकेंगी। भारत सरकार ने 2030 तक ईवी को 30 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में लिथियम सबसे आवश्यक धातु है।

झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह की धरती से निकलने वाले अभ्रक की चमक कभी पूरी दुनिया तक पहुंचती थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में न तो अभ्रक की डिमांड रही और न ही उसकी खदानें बचीं। लेकिन इसी धरती के भीतर खोजे गए बेशकीमती खनिज लिथियम के बड़े भंडार ने देश में बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अपार संभावनाएं जगाई हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) ने भू-तात्विक सर्वेक्षण में पाया है कि कोडरमा और गिरिडीह में लिथियम के अलावा कई दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। पूरी दुनिया में आने वाले वर्षों में जीरो कार्बन ग्रीन एनर्जी के जिन लक्ष्यों पर काम चल रहा है, उसमें लिथियम को गेमचेंजर मिनरल के तौर पर देखा जा रहा है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोबाइल फोन, सौर पैनल, पवन टरबाइन और अन्य रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में किया जाता है।

कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बाद अब झारखंड तीसरा राज्य

जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल में कर्नाटक में 1600 टन और इसके बाद जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार खोजा था। अब झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह के अलावा पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में इस बेशकीमती धातु के उत्खनन की संभावनाओं पर काम चल रहा है। झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया ब्लॉक और उसके आसपास जियोकेमिकल मैपिंग में यहां उपलब्ध लिथियम, सीज़ियम और अन्य तत्वों में हाई कन्स्ट्रेशन (उच्च सांद्रता) पाया गया है। फिलहाल देश का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग अभी भी अपनी लिथियम आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। अभी हम लिथियम का आयात मुख्य तौर पर चीन से करते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक ईवी को 30 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में लिथियम सबसे आवश्यक धातु है। इसलिए लिथियम के उत्खनन की संभावनाओं पर सरकार का खास तौर पर फोकस है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत होगी कम

ऐसे में कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बाद झारखंड में लिथियम के भंडार की खोज को भविष्य की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि लिथियम का भंडार देश में मिलने से चीन पर निर्भरता खत्म होगी। अभी चीन से भी बैटरी का आयात किया जा रहा है। इससे ईवी की कीमत काफी अधिक है। देश में लिथियम मिलने से बैटरी की कीमत कम होगी। इससे इलेक्ट्रि गाड़ियों के दाम में बड़ी कमी आएगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रि गाड़ियों की कीमत में करीब 40 से 50 फीसदी हिस्सा बैटरी का होता है। बीते जून महीने में पैन एशिया मेटल्स लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पॉल लॉक ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और झारखंड में लिथियम खनन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की थी। सीएम ने कहा था कि झारखंड सरकार नियमों के अनुसार लिथियम प्रोडक्शन की संभावनाओं पर योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी।

इन जिलों में मिला खदान

जीएसआई के सर्वे के अनुसार झारखंड के कोडरमा के तिलैया ब्लॉक और ढोढ़ाकोला-कुसुमा बेल्ट में लिथियम के अलावा सिजियम, गिरिडीह के गांवा ब्लॉक और कोडरमा के पिहरा बेल्ट में एलआई (ली), सिजियम, आरईई और आरएम जैसे धातुओं का भंडार होने की संभावनाएं हैं। विगत 29 सितंबर को झारखंड सरकार के भूतात्विक पर्षद की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में लिथियम की खोज के परिणामों पर चर्चा की गई। सरकार ने राज्य में लिथियम खनन की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। निवेशकों ने भी इसे लेकर अपनी रुचि प्रदर्शित की है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है तो इससे इलेक्ट्रिक बैटरियां सस्ती होंगी और अंततः इलेक्ट्रिक कारों की कीमत भी कम हो सकेंगी।

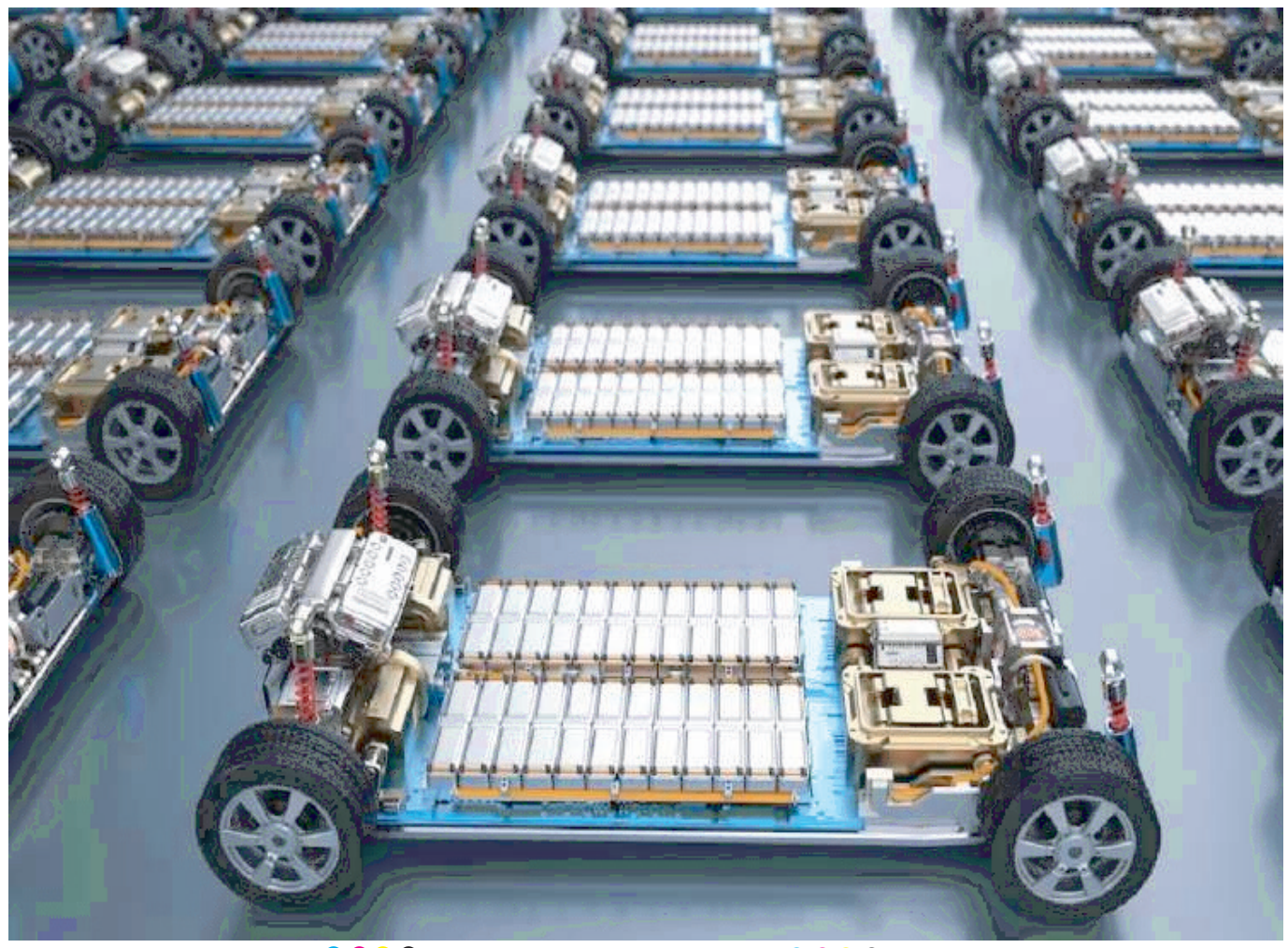

प्रवासियों की विकास में नई भूमिका

डा. जयंतीलाल भंडारी

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत के प्रवासियों के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताएं कम हुई थी। इसी तरह से भारत ने भी विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के हर दुख-दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाई है'

यकीनन इस समय दुनिया के विभिन्न देशों में प्रभावी भूमिका निभा रहे भारतवंशी और प्रवासी भारतीय भारत के आर्थिक और तकनीकी विकास में भी अपने अभूतपूर्व योगदान के नए अध्यायों के साथ वैश्विक मंच पर भारत के हितों की जोरदार हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में कनाड़ा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत की छवि खराब करने के उद्देश्य से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान की कनाडा और अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न देशों के प्रवासी भारतीयों ने निंदा की और भारत के द्वारा आतंकवाद को समाप्त करने के प्रयासों को शक्ति प्रदान की। इतना ही नहीं, इस समय प्रवासी भारतीय भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के मद्देनजर विशेष संगठन बनाकर नई अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 2023 में भारत की जी-20 की अध्यक्षता और विगत 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में प्रवासी भारतीयों के संगठन 'इंडियास्पोरा' का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इंडियास्पोरा भारत के विकास में अहम योगदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में अमेरिका में स्थापित एक ऐसी गैर-लाभकारी संस्था है, जो करीब 20 देशों में सक्रिय रूप से मजबूती के साथ काम कर रही है। यह संगठन दुनियाभर के विभिन्न देशों के प्रवासी भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायी बन गया है। इस संगठन का कहना है कि भारत ने अपनी आजादी के 76 साल का संतोषजनक सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा भारत के बढ़ाए गए गौरव और प्रवासी भारतीयों के लिए किए गए विशेष प्रयासों से भारतवंशियों तथा प्रवासियों का भारत के लिए सहयोग और स्नेह लगातार बढ़ा है।

ऐसे में अब भारत के तेज विकास और भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के मद्देनजर भारतवंशियों व प्रवासियों द्वारा तन-मन-धन से आगे बढना चाहिए। यह कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया के अनेक देशों में प्रभावी भारतवंशी राजनेता अपने-अपने देशों को आगे बढ़ाते हुए विश्व के समक्ष भारत के चमकते हुए चेहरे हैं और ये हरसंभव तरीके से भारत के विकास में अपना अहम योगदान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन राजनेताओं में हाल ही में 14 सितंबर को सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले भारतवंशी थर्मन शनमुगरत्नम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक. आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा,

अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपुन, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी आदि के नाम उभरकर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह दुनिया में वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संस्थानों, आईटी, कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचे प्रवासी इन विभिन्न क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने के नए अध्याय लिख रहे हैं। भारतवंशी अमेरिकी 63 वर्षीय अजय बंगा ने चार माह पहले विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में पांच साल के लिए कार्यभार संभाला है। वे इस संस्था की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतवंशी है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, नोवार्टिस वसंत नरसिम्हन, एडोब के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, स्टारबक्स के लक्ष्मण नरसिम्हन, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के रेशमा केवलरमानी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, कैडेंस डिजाइन सिस्टम के अनिरुद्ध देवगन, पालो अल्टो नेटवर्क के निकेश अरोड़ा, वीएमवेयर के रंगराजन रघुराम, इमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी के सुरेंद्रलाल करसनभाई, माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी के गणेश मूर्ति आदि अपनी प्रतिभा व कौशल से कारोबार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर रहे हैं और भारत के विकास में भी रेखांकित करने वाला योगदान दे रहे हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशों की नई संस्कृति में ढलकर इस तरह की सफलता हासिल करना आसान नहीं होता है। वास्तव में भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों के एक पूरे जीवन को आकार देने तथा ऊंचे पदों पर कार्य की रणनीति बनाने तथा नेतृत्व की भूमिका के मद्देनजर उन्हें मूल रूप से मिले हुए भारतीय संस्कार और भारतीय मूल्यों पर आधारित मूलमंत्र अहम भूमिका निभाते हैं। यद्यपि चीनी प्रवासी भी दुनिया के कोने-कोने में हैं, लेकिन वे भारतीय प्रवासियों की तरह शीर्ष वैश्विक संस्थानों राजनीति और उद्योग-कारोबार में वैसी प्रभावी भूमिका नहीं रखते हैं। ज्ञातव्य है कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, जिसकी संख्या लगभग 3.2 करोड़ है। मोटे तौर पर प्रवासी भारतीयों में भारतवंशी (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन), नॉन रेसीडेंट इंडियन (एनआरआई) और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भारतीय एनआरआई की संख्या करीब 1.34 करोड़ है और ये भारत में अपने संबंधित क्षेत्र में मतदान के पात्र हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में विभिन्न प्रवासी समूहों में सबसे अधिक आय भारतीयों की है। भारतीय मूल के लोग अमेरिकी आबादी का एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के कर खजाने का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह आर्थिक ताकत भारतीय प्रवासियों को अमेरिका-भारत गलियारे में द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर एक शक्तिशाली आवाज उठाने में सक्षम बनाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयों की औसत आय राष्ट्रीय औसत से डेढ़ गुना है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि प्रवासी भारतीयों का भारत के साथ स्नेह और सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और ये भारत को धन भेजने के मामले में अन्य सभी देशों के प्रवासियों से बहुत आगे हैं। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलमपेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के मुताबिक विदेश में कमाई करके अपने देश में धन (रेमिटेंस) भेजने के मामले में वर्ष 2022 में भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे आगे रहे हैं। वर्ष 2022 में प्रवासी भारतीयों के द्वारा भेजी जाने वाली रकम 100 अरब डॉलर से भी अधिक की रही है। वर्ष 2021 में प्रवासियों ने करीब 87 अरब डॉलर की राशि स्वदेश भेजी। प्रवासियों से धन प्राप्त करने वाले दुनिया के विभिन्न देशों की सूची में भारत वर्ष 2008 से अब तक पहले क्रम का देश बना हुआ है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अतीत में जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट आई, तब प्रवासियों ने मुक्त हस्त से भारत के विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में सहयोग दिया है। जब वर्ष 1998 में भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पोखरण-2 विस्फोट के बाद अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के द्वारा भारत पर लगाए गए तब आर्थिक प्रतिबंधों को वापस कराने में प्रवासी भारतीयों ने देश का सबसे ज्यादा साथ दिया और दुनिया का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत के प्रवासियों के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताएं कम हुई थी। इसी तरह से भारत ने भी विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के हर दुख-दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। हम उम्मीद करें कि जिस तरह 9-10 सितम्बर को भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 को अभूतपूर्व सफलता दिलाने में प्रवासी भारतीयों की भी अहम भूमिका रही है, उसी तरह अब भारतवंशी और प्रवासी भारतीय वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे।

संपादक की कलम से

बलात्कार से बिक्री तक

महाकाल ज्योतिर्लिंग, महादेव और मंदिरों के शहर उज्जैन में 12 वर्षीय नाबालिग कन्या के साथ न केवल क्रूर बलात्कार किया गया, बल्कि उसे घायल कर लावारिस छोड़ दिया गया। उस बच्ची की रक्षा करने न तो कोई दैवीय करिश्मा हुआ और न ही किसी नागरिक ने उसकी पीड़ा साझा कर मदद करने की कोशिश की। उसे अस्पताल तक पहुंचाने की इनसानियत भी नदारद रही। बच्ची रोती-बिलखती, दर-दर गुहार करती रही, लेकिन उस कथित पवित्र शहर का असली चेहरा लगातार बेनकाब होता रहा। इतनी बेरुखी, संवेदनहीनता, तटस्थता सामने आती रही कि एक जिंदगी मर रही है, लेकिन घरों के दरवाजे बंद हैं! यही घोर कलियुग है। यह हमारे समाज और देश में हररोज घट रहा है। हररोज बलात्कार और सामूहिक दुष्कर्म, हत्या अथवा जला देने के जो औसत, दर्ज आंकड़े सामने आते रहे हैं, वे बेहद कम हैं। यह दरिंदगी, हवस और पाशविकता हम राजधानी दिल्ली में भी देखते रहे हैं। अभी हाल ही में 'आज तक' ने छिपे कैमरे से एक ऑपरेशन किया। मन-मस्तिष्क चीत्कार कर उठा। बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। मामा, चाचा, मौसी आदि परिजन ही घर की बेटियां बेच रहे हैं। लाखों रुपए में बेटियों-बहनों की सौदेबाजी की जा रही है। हलफनामे भरे जा रहे हैं। ग्राहकों को तसल्ली दी जा रही है कि आप लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हो! भारत के भीतर का एक और भारत यह भी है। एक रपट ने खुलासा किया है कि करीब 13 लाख बेटियां, बहनें, माताएं और देश की महिलाएं गायब हैं, लापता हैं।

वे स्त्रियां कहां गईं? कैसे लापता हुईं? पुलिस-व्यवस्था ने क्या किया? उन्हें कौन 'दरिंदे' लूट गए? क्या वे भारत की नारियां 'वेश्यालय' तक पहुंचा दी गई हैं अथवा विदेशों में तस्करी की गई हैं? बेहद झकझोर देने वाले सवाल हैं। किसी देश की 13 लाख कन्याएं और महिलाएं लापता हो जाएं और यह मुद्दा संसद में न उठे, इससे बड़ी हैरानी और संवेदनहीनता क्या होगी? संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण अब एक कानून बन चुका है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है और महिलाओं का व्यापक समर्थन हासिल करने को व्यग्र हैं। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के वाहन के चारों ओर महिलाओं का घेरा बनाया जाने लगा है। स्पष्ट अर्थ है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा को महिलाओं का समर्थन और सहयोग सुनिश्चित किया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री से हमने आज तक इस सरोकार के शब्द तक नहीं सुने कि 13 लाख स्त्रियां क्यों, कहां गायब कर दी गईं? वे सभी देश की सम्मानित नागरिक हैं, आधी-शक्ति की प्रतीक हैं और कई लाख तो मतदाता भी होंगी! वह देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी संसाधन, स्रोत और शक्तियां उन्हें संविधान ने प्रदान की हैं। जिस देवनगरी में नाबालिग की इज्जत तार-तार की गई थी, वह मध्यप्रदेश का ही एक शहर है, जहां भाजपा की सरकार है।

प्रधानमंत्री उस राज्य में वोट मांग रहे हैं, सत्ता को बरकरार रखने के प्रयास और प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को तलब कर पूछा क्यों नहीं कि महादेव के शहर में ऐसा क्यों हुआ? आज मद्रास उच्चन्यायालय का फैसला आया है, जिसमें तमिलनाडु के 215 अफसरों, कर्मचारियों को पुनः दंडित किया गया है। 1992 में वाचथी गांव में 18 महिलाओं के साथ दरिंदगी की हदें पार की गईं। 32 साल बाद फैसला आया है। इस बीच 54 आरोपितों की मौत भी हो चुकी है। तब 8 माह की गर्भवती औरत और 13 साल की बच्ची को भी दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। यह देश का कैसा न्याय है? दुष्कर्म, क्रूरता, हवस के मामलों में भी 32 साल तक मामला अदालतों में लटका रहेगा, तो फिर किसकी जिंदगी सुरक्षित मानी जा सकती है? राक्षस तो किसी की भी जिंदगी में टकरा सकते हैं। किसी की भी इज्जत से खिलवाड़ कर सकते हैं? फिर महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, शिक्षा आदि के जुमले क्यों उछाले जाते रहे हैं? यदि बच्चियां बचेंगी, तो फिर आगे बढ़ पाएंगी, पढ़-लिख सकेंगी! उनकी इज्जत पर ही हमले जारी रहेंगे, तो फिर हमारा देश 'भारत महान' कैसा?

राय

शव संवाद-12

लाशें निपटाते बुद्धिजीवी की खबर जनता, प्रशासन और सरकार तक पहुंच गई थी। जनता खुश थी कि बुद्धिजीवी अब शमशानघाट के चक्करों में ही रहेगा। सरकार ने प्रशासन से रिपोर्ट मांग ली थी कि बुद्धिजीवी कहीं मरने के आंकड़ों में उसे बदनाम तो नहीं कर रहा। सत्तारूढ़ दल यह तो मान चुका था कि कोई बुद्धिजीवी उसका समर्थक नहीं हो सकता, लिहाजा कहीं विपक्षी बुद्धिजीवी लाशों में कोई मुद्दा ही न ढूंढ ले। खैर प्रशासन ने जांच बैठा दी, तो पहली बार शमशानघाट तक उसकी निगाह पहुंच गई। वहां रोज शवों के तांते में प्रशासन अपने खिलाफ मुर्दों को मुद्दा न बनने की हिदायत देकर कार्रवाई पूरी करता, बल्कि मरने के आंकड़ों में कई भेद मिटाए जा रहे थे। बुद्धिजीवी खुश था कि उसके बहाने प्रशासन चुस्त हो गया। फिर भी अपने विचारों की धूप में वह समाज की हर राह पर घूमता रहता। एक दिन प्रशासन ने घोषणा कर दी कि देश का अंतिम बुद्धिजीवी मर गया। उसने पहली बार संवेदना प्रकट करते हुए प्रशासन, सरकार और जनता को देखा। क्योंकि प्रशासन कह रहा था, इसलिए उसे अपने जिंदा होते हुए भी मरने का भ्रम हो गया। खबर पता लगते ही वह सचिवालय पहुंच गया। प्रदेश और देश की नौकरशाही से रूबरू होकर वह खुद को जिंदा साबित कर रहा था, लेकिन फाइल मना कर रही थी। वहां बैठा प्रशासन मुस्करा रहा था कि कैसे जीता-जागता बुद्धिजीवी भी फाइल की वजह से मर सकता था। अब उसे खुद को जिंदा साबित करना था, तो तरीके ढूंढने लगा। उसे पहली बार पता चला कि जिंदा होने का सबूत मरने से कहीं महंगा और कष्टदायी है। उसे छोटे से छोटा बाबू और बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट एक जैसा लगा।

बुद्धिजीवी सोचने लगा, 'देश के इतने बड़े यानी आईएएस अधिकारी के चयन की कीमत तो अदने से बाबू के बराबर ही है। बाबू ज्यादा समझदार लगा क्योंकि उसने वादा किया कि वह उसे जिंदा घोषित करवा देगा। बाबू ने फाइल से एक नाम निकाला जो कि एक ब्यूरोक्रेट से मिलता था। दोनों के नाम एक जैसे थे, लिहाजा उसे बताया गया कि लापता ब्यूरोक्रेट की लाश ढूंढ लाओ, तो जिंदा घोषित हो जाओगे। बुद्धिजीवी को आज तक प्रशासन लापता ही मिला था, तो यहां सवाल एक नौकरशाह यानी लापता आईएएस आफिसर का था। ढूंढते-ढूंढते वह प्रशासन की गलियों से इतना वाकिफ हो गया कि लोगबाग उसे भी प्रशासन का कारिंदा समझने लगे। अचानक एक दिन उसे पुरानी फाइलों के पीछे अब तक की जांच रिपोर्टों में ईमानदार साबित हुए ब्यूरोक्रेट्स का पता मिल गया। वह ढूंढते-ढूंढते अपने नाम के ब्यूरोक्रेट के पास पहुंच गया। ब्यूरोक्रेट ममीफाइड था। उसे मृत घोषित नहीं किया गया था, बल्कि मसाला लगाकर उसकी देह को उपस्थित कर रखा था। बुद्धिजीवी उसे छीनने की फिराक में यह भूल गया कि यह उसकी आंखों का धोखा है। नौकरशाह असल में जब तक डमी या बाद में ममी की तरह रहे, तब तक जिंदा है। उसकी अंगुली लगते ही ब्यूरोक्रेट की देह शव में बदल गई। उसे गोपनीय तरीके से बुद्धिजीवी को सौंपा गया ताकि मरे प्रशासन की गवाही न मिले। 'आप व्यक्तित्वशून्य क्यों हुए।' पुराने आईएएस अधिकारी के शव ने व्यथा प्रकट की, 'हम रेंगते नहीं। हम भी चल सकते हैं, लेकिन चलें तो सरकारें घुटनों पर सवार हो जाती हैं, हम रेंगना नहीं चाहते, लेकिन लाल कालीन बिछाते-बिछाते हमें उसकी गंध इतनी अच्छी लगती है कि झुक-झुक कर रीढ़विहीन हो गए हैं।' बुद्धिजीवी ने ब्यूरोक्रेट के शव को किसी तरह कंधे पर उठा लिया और शमशानघाट पहुंच गया, लेकिन वह गेट के भीतर घुस नहीं पा रहा था। वहां प्रशासन का निर्देश चस्पां था, 'कोई भी व्यक्ति बिना पहचान पत्र या आधार कार्ड के शव को लाएगा, तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा।' बुद्धिजीवी हैरान था कि ब्यूरोक्रेट की लाश उठाकर भी वह प्रशासनिक निर्देशों के चंगुल से नहीं छूट पाया।

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन कोष

चूंकि राज्य धन की कमी के कारण मौजूदा स्थिति से निपटते समय एक कठिन सबक सीख रहा है, इसलिए यह निस्संदेह स्पष्ट है कि राज्य बाहरी मदद पर भरोसा नहीं कर सकता है। हमें अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने होंगे और अपनी प्रादेशिक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी। शुरुआत के लिए, वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए जल उपकर की तरह, हिमाचल में आने वाले हर पर्यटक से आपदा आकस्मिकता निधि के लिए उपकर जुटाया जा सकता है। अत्यधिक पर्यटन के बोझ से जूझ रहे बहुत से देश और शहर पर्यटकों से भारी कर वसूल रहे हैं। जाहिर है हिमाचल को भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह पैसा प्रदेश वासियों के जीवन को सुरक्षित बनाने में लगाया जाए'

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की एक ऐसी सच्चाई है जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें इस नई वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाएं अब हमारे आंगन पर अक्सर दस्तक देती रहेंगी और हमें आने वाले लंबे समय तक उनसे निपटना होगा। इस नई वास्तविकता को देखते हुए वर्तमान में एकमात्र चीज जो मायने रखती है, वह यह है कि हम भविष्य में इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद को कितनी अच्छी तरह तैयार करते हैं। अगस्त महीने में हिमाचल ने जिस त्रासदी की पीड़ा सही, वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लगभग रोजाना होने वाली तबाही की घटनाओं से अलग नहीं है। आज सारा विश्व बाढ़, सूखा, आग, भूस्खलन, तूफान, अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी के प्रकोप से जूझ रहा है। विघटन और विनाश की यह लीला मानव सभ्यता का अंतिम पड़ाव तो नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे जीवन को बड़े पैमाने पर बदलने जा रहा है। कोई भी प्राकृतिक आपदा अघोषित रूप से आती है, इसलिए हम इसे अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं और इसके प्रकोप से बचने के लिए केवल प्रार्थना पर आश्रित रहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन काफी समय से हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप के आने का संकेत दे रहे हैं। ऐसी घटना के लिए हमारे पास कोई आपदा तैयारी योजना नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि भूकंप आज आ सकता है या अगले कई दशकों के बाद भी आ सकता है।

इसलिए हम गणनात्मक जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अवैज्ञानिक निर्माण जारी रखते हैं। अपने शहरों पर और अधिक कंक्रीट भरते हैं और अधिक बांधों व जलाशयों का निर्माण जारी रखते हैं, इत्यादि। लेकिन आज मौसम के प्रकोप से उत्पन आपदाएं भूकंप जितनी विनाशक होने की क्षमता रखती हैं और निश्चित रूप से यह निरंतर दस्तक भी देती रहेंगी। ऐसी परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास मौसम की अनिश्चितताओं से लडने के लिए एक ठोस योजना हो। लेकिन योजना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसे क्रियान्वित करने के लिए बजट न हो तो प्रयास बेकार जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दिशा में उन्मीद का जो दिया जगाया है, वह लम्बे समय तक हिमाचल की पहाडियों को आलोकित करता रहेगा। अपनी सारी बचत सीएम सहायता कोष में दान करके उन्होंने दूसरों के लिए एक उदाहरण तो स्थापित किया ही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता का भी संदेश है। यह अत्यधिक दुःख की बात है कि राज्य सरकार को हिमाचल में हाल ही में हुई तबाही को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करने और धन जारी करने के लिए केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बरसात के महीनों में हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जो लोग पीड़ित हैं, वे निश्चित रूप से धीरे-धीरे अपना जीवन वापस समेट ही लेंगे, लेकिन परित्यक्त महसूस करने का बोझ उठाए बिना नहीं, अगर समय पर मदद उन तक पहुंचने में विफल रहती है।

मुख्यमंत्री की तरह प्रदेश के अन्य लोग भी हरसंभव तरीके से राहत कार्यों में योगदान दे रहे हैं, लेकिन त्रासदी के पैमाने को देखते हुए कोई भी प्रयास कम पडना तय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमाचल आपदा के मलबे से कृतसंकल्प के साथ उभरेगा, लेकिन भविष्य की नींव तो ठोस तथ्यों पर ही रखनी होगी। चूंकि राज्य धन की कमी के कारण मौजूदा स्थिति से निपटते समय एक कठिन सबक सीख रहा है, इसलिए यह निस्संदेह स्पष्ट है कि राज्य बाहरी मदद पर भरोसा नहीं कर सकता है। हमें अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने होंगे और अपनी प्रादेशिक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी।

चिंतन विचार

बापू की पत्रकारिता के सिद्धांत

कड़वा सच यह है, पत्रकारिता के तथ्यों को क्रॉस चेक करने वाला बापू का यह सिद्धांत बिसरा दिया गया है, लेकिन पाठकों को यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। बापू ने बार-बार पत्रकारों को भी उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई है। उन्होंने लिखा था, अगर सरकार को नाखुश करने वाला कुछ प्रकाशित हो भी गया है, तो भी संपादक को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। बापू की दृष्टि में संपादक का कद बड़ा था। बड़ा होना भी चाहिए। बापू का प्रसिद्ध कथन है, हम जो आज करते हैं, उस पर भविष्य निर्भर करता है'

अहिंसा के पथ-प्रदर्शक, सत्यनिष्ठ, समाज सुधारक और महात्मा के रूप में विश्वविख्यात बापू सबसे पहले सफल पत्रकार थे। बापू की पत्रकारिता भी उनके गांधीवादी सिद्धांतों की मानिंद है। बापू का स्पष्ट मानना था, पत्रकारिता की बुनियाद सत्यवादिता के मूल में निहित होती है। असत्य की तरफ उन्मुख होकर पत्रकारिता के उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बापू का यह दृष्टिकोण इस बात की पुष्टि करता है, उनकी पत्रकारिता और व्यावहारिक जीवन के सिद्धांतों में किसी तरह का दोहरापन नहीं रहा है। सवाल यह है, क्या आज की वैश्विक पत्रकारिता इन मापदंडों पर खरी उतर रही है। पत्रकारिता में बापू के योगदान की ऐतिहासिकता पर नजर डालें तो उनकी पत्रकारिता का श्रीगणेश ही विरोध की निज अभिव्यक्ति से हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में अखबार को लिखे पत्र को बापू की पत्रकारिता का पहला कदम माना जा सकता है। बापू की प्रखर लेखनी का लोहा मानते हुए एक अंग्रेजी के लेखक ने तो यहां तक कहा, गांधी के संपादकीय लेखों के वाक्य थॉट ऑफ दि डे के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

ऐसी थी, बापू की लेखनी की ताकत। यह बापू की पत्रकारिता के अद्वितीय उदाहरण हैं। बापू की पत्रकारिता डगर में भाषाई दायरे कभी अवरोध नहीं बने। वह समय और अवसर के अनुकूल हिंदी/उर्दू/अंग्रेजी/गुजराती में लेखन कर लिया करते थे। दाएं हाथ से हिंदी/उर्दू लिखने वाले बापू बाएं हाथ से शानदार अंग्रेजी लिखते थे। सवाल यह है, हममें से कितने बापू की इन विशेषताओं का अनुसरण कर रहे हैं। बापू की नजर में पत्रकारिता का मकसद जन जागरण था। वह जनमानस की समस्याओं को मुख्यधारा की पत्रकारिता में रखने के प्रबल पक्षधर थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गुलामी की परिस्थितियों से प्रबल बापू ने सत्य, अहिंसा के समानांतर पत्रकारिता और लेखनी को भी अपना हथियार बनाया। दि इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन में विचारों से ओत-प्रोत हजारों लेख लिखे। इनमें बापू के मूल्य, आदर्श, सिद्धांत साफ-साफ परिलक्षित होते हैं। बापू का साफ मानना रहा, पत्रकारिता का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को अपनाना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भीकतापूर्वक प्रकट करना है। वह मानते रहे, ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। प्रश्न यह है, क्या हम बापू के सपनों की पत्रकारिता को सच में अमलीजामा पहना रहे हैं या नहीं? बापू पत्रकारिता को दो रूपों में विभाजित करते हैं- एक, व्यावहारिक पत्रकारिता और दूसरी लोकसेवी। बापू की साफ मान्यता थी, पत्रकारिता को व्यवसाय बनाने से वह दूषित हो जाती है और लोकसेवा के लक्ष्य से भटक जाती है। बापू

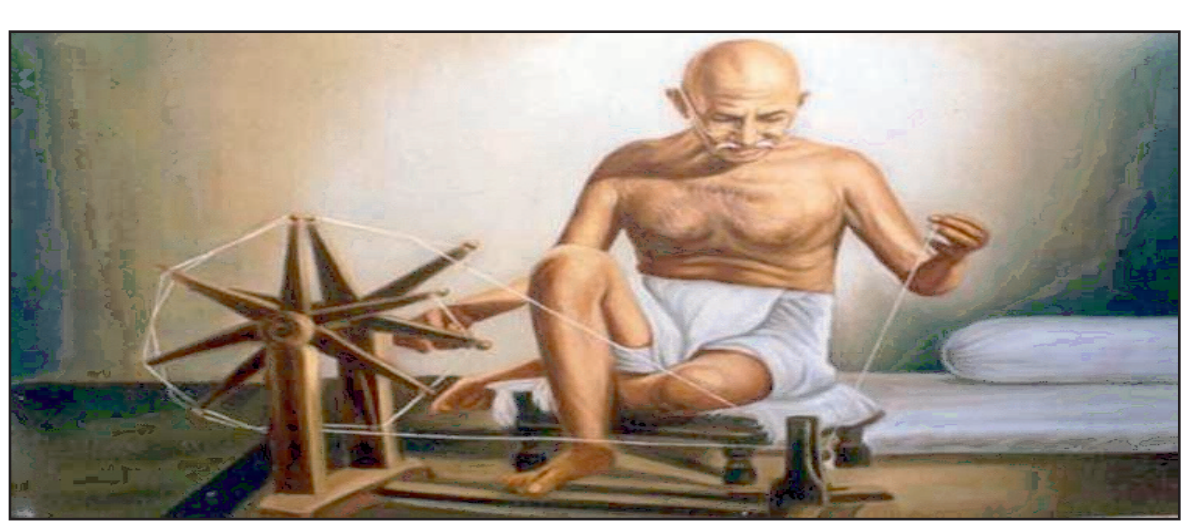

समाचारपत्रों की शक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों में पहचानते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' में लिखा है- समाचार पत्र सेवाभाव से ही चलने चाहिए। समाचार पत्र एक जबर्दस्त शक्ति है, किन्तु जिस प्रकार निरंकुश पानी का प्रवाह गांव के गांव डुबो देता है, उसी प्रकार प्रलय का निरंकुश प्रवाह भी नाश करता है। यदि अंकुश कहर से आता है तो वह निरंकुशता से भी विषैला होता है। 21वीं सदी में पत्रकारिता और लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचाने वाली अनेक घटनाएं घटी हैं। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली पेड न्यूज की कुप्रथा सामने आई है। फेक न्यूज का भी भयावह रूप किसी से छुपा नहीं है। फिर वही सवाल, क्या हम सत्यनिष्ठा से पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं? बापू ने अंतिम समय तक पत्रकारिता को कभी किसी व्यक्ति विशेष या संगठन का मोहरा नहीं बनाया। क्या आज ऐसा है? वह अपने लिखे एक-एक शब्द पर मनन करते थे। सकारात्मक और नकारात्मक नतीजों के बारे में सोचते थे। सत्य की कसौटी पर खरा उतरने वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे।

बापू साथ ही पाठकों को यह अधिकार भी देते थे, वे समाचार पत्र पर पैनी नजर रखें। कहीं कोई अनुचित या झूठी खबर तो नहीं छपी है। अविवेकपूर्ण भाषा का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। क्या आज पाठकों के पास बापू वाला अधिकार है? बापू का मानना था, संपादक पर पाठकों का चाबुक रहना चाहिए, जिसका उपयोग संपादक के बिगडने पर हो सके। कड़वा सच यह है, पत्रकारिता के तथ्यों को क्रॉस चेक करने वाला बापू का यह सिद्धांत बिसरा दिया गया है, लेकिन पाठकों को यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। बापू ने बार-बार पत्रकारों को भी उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई है। उन्होंने लिखा था, अगर सरकार को नाखुश करने वाला कुछ प्रकाशित हो भी गया है, तो भी संपादक को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। बापू की दृष्टि में संपादक का कद बड़ा था। बड़ा होना भी चाहिए। बापू का प्रसिद्ध कथन है, हम जो आज करते हैं, उस पर भविष्य निर्भर करता है। बापू ने हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित इंडियन ओपिनियन को लेकर अपने बुलंद इरादे साफ कर दिए थे। बापू ने लिखा था, इंडियन ओपिनियन की जरूरत के बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। भारतीय समाज दक्षिण अफ्रीका के राजकीय शरीर का निर्जीव अंग नहीं है, उसे जीवित अंग सिद्ध करने के लिए बहुभाषी यह समाचार पत्र निकाला गया है। आज भारतीय ही नहीं, बल्कि विश्व के समूचे पत्रकारिता जगत को जरूरत है, वह बापू के मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों को पढ़ें, समझें और आत्मसात करें। अगर ऐसा कर लेंगे तो बापू को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

प्रो. श्याम सुंदर भाटिया

क्रेडिट कार्ड का उपयोग करे बिना भी कम हो जाती है लिमिट, बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीका

परिवहन विशेष न्यूज

कई बार देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड यूजर की ओर से कार्ड का इस्तेमाल न होने पर भी उसकी लिमिट कम हो जाती है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्रेडिट कार्ड कंपनी को नियामकों की ओर से दी गई लिमिट होती है। इसे मैनेज करने के लिए कंपनियों उन यूजर्स की लिमिट घटा देती हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

नई दिल्ली। आज के समय में क्रेडिट कार्ड मिलना काफी आसान है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आसानी से आपको किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। लेकिन हर क्रेडिट कार्ड के साथ एक लिमिट आती है, जिसे क्रेडिट लिमिट कहा जाता है।

आमतौर माना जाता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट का अधिकतम 30 प्रतिशत ही उपयोग करना चाहिए। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर नहीं होता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बनी रहती है। वहीं, जो लोग बार-बार पूरी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते है। क्रेडिट कार्ड कंपनी उनकी लिमिट भी कई बार कम कर देती है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड लेकर उसका उपयोग भी नहीं करते हैं तो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी लिमिट कर सकती है।

क्रेडिट कार्ड उपयोग न करने पर क्यों घट जाती है लिमिट?

नियामकों की ओर से हर क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक को क्रेडिट लिमिट दी जाती है, जिसके अंदर रहकर ही बैंक को क्रेडिट कार्ड जारी करने होते हैं। इसे मैनेज करने के लिए कई बार बैंक उन ग्राहकों की क्रेडिट लिमिट कम कर देते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं।

क्रेडिट लिमिट को बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीका

ऐसे में अगर आप इससे बचना चाहते तो अपने क्रेडिट कार्ड को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। इसके लिए आप महीने में एक लेनदेन करने के तरीके को भी अपना सकते हैं। इससे आपका क्रेडिट कार्ड भी एक्टिव रहेगा और आपकी लिमिट भी कम नहीं होगी।

क्रेडिट स्कोर अच्छा करने में मदद करती है क्रेडिट लिमिट

क्रेडिट लिमिट आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने में मदद करती है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30 प्रतिशत ही उपयोग करना चाहिए। 750 या उससे अधिका का क्रेडिट स्कोर आदर्श माना जाता है।

ईपीएफओ ने जारी अलर्ट! फर्जी कॉल और एसएमएस से रहें सावधान

EPFO की ओर से कहा गया कि ईपीएफओ और उसके कर्मचारी कभी भी मैसेज फोन ई-मेल व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर किसी भी सदस्य का निजी विवरण नहीं मांगते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मैसेज फोन ई-मेल व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर मांगता है तो आप उसकी शिकायत पुलिस की साइबर अपराध शाखा में जाकर कर सकते हैं।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी सदस्यों के लिए अटर्ल जारी करते हुए कहा कि ईपीएफओ कभी भी किसी सदस्य की निजी जानकारी फोन, ई-मेल और सोशल मीडिया के जरिए नहीं मांगता है। कभी भी किसी को भी इन सभी माध्यमों से कोई निजी जानकारी शेयर न करें।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फेक कॉल और मैसेज से सावधान रहें। ईपीएफओ की ओर से कभी भी सदस्यों से फोन, ई-मेल और सोशल मीडिया के जरिए कोई भी निजी जानकारी नहीं मांगी जाती है।

इसके साथ ही ईपीएफओ ने एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ था कि 'सावधान रहें, सतर्क रहें', कभी भी अपना UAN/पासवर्ड/पैन/आधार/बैंक खाता विवरण/ओटीपी या कोई अन्य व्यक्तिगत या वित्तीय विवरण किसी के साथ साझा न करें। ईपीएफओ या उसके कर्मचारी कभी भी मैसेज, फोन, ई-मेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर ये विवरण नहीं मांगते हैं।

साइबर अपराध शाखा में दर्ज कराएं शिकायत

ईपीएफओ द्वारा पोस्टर में कहा गया कि इस तरह की जानकारी मांगने वाले फर्जी कॉल/संदेशों से सावधान रहें और अगर इस तरह की जानकारी कोई आपसे मांगता है तो पुलिस/साइबर अपराध शाखा को तुरंत रिपोर्ट करें।

EPFO की हेल्पलाइन से संपर्क करें

इसके अलावा एफपीएफओ की पीएफ, पेंशन या ईडीएलआई योजनाओं के बारे में जानने के लिए ईपीएफओ हेल्पलाइन 14470 पर कॉल कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक खुली रहती है। आप यहां अंग्रेजी के अलावा हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली और असमीया में भी जानकारी ले सकते हैं।

गूगल ने भारत में शुरू किया क्रॉमबुक्स का प्रोडक्शन, सीईओ सुदंर पिचाई बोले- छात्रों को मिलेगा फायदा

Google Chromebooks की मैन्यूफैक्चरिंग एचपी की चेन्नई के पास स्थित फ्लैक्स फैसिलिटी में होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए गूगल के सीईओ सुदंर पिचाई ने कहा कि हम एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक्स की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। यह भारत में बनने वाली पहली क्रोमबुक्स होंगी। इससे भारतीय छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित कम्प्यूटिंग करना आसान हो जाएगा।

नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने पीसी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक्स की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर दी है। एचपी की ओर से ये जानकारी सोमवार को दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, क्रोमबुक्स डिवाइस की मैन्यूफैक्चरिंग एचपी की चेन्नई के पास स्थित फ्लैक्स फैसिलिटी में किया जाना है। जहां कंपनी पहले से ही लैपटॉप और डेस्कटॉप का उत्पादन कर रही है।

सुदंर पिचाई ने किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए गूगल के सीईओ सुदंर पिचाई ने कहा कि हम एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक्स की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। यह भारत में बनने वाली पहली क्रोमबुक्स होंगी। इससे भारतीय छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित कम्प्यूटिंग करना आसान हो जाएगा।

HP ने पीएलआई स्कीम के लिए कर चुकी है आवेदन

एचपी उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने आईटी हार्डवेयर के लिए लाई गई 17,000 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम के लिए आवेदन किया है। एचपी के प्रवक्ता की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि गूगल की क्रोमबुक का उत्पादन भारत में शुरू हो गया है।

दोनों कंपनियों ने संतुक्त बयान किया जारी

गूगल और एचपी की ओर से एक संयुक्त बयान में कहा गया कि क्रोमबुक्स K-12 शिक्षा में एक लीडिंग डिवाइस है। यह पूरी दुनिया में 5 करोड़ छात्रों और शिक्षकों की मदद कर रहा है।

एचपी 2020 से भारत में मैन्यूफैक्चरिंग ऑपरेशन का विस्तार कर रहा है। मौजूदा समय में भारत में P EliteBooks, HP ProBooks, and HP G8 series notebooks का प्रोडक्शन कर रहा है।

शॉपिंग क्रेडिट कार्ड पर ऑफर्स का लालच पड़ सकता है भारी उपयोग करने से पहले ध्यान रखें इसके नुकसान

परिवहन विशेष न्यूज

क्रेडिट कार्ड के अलावा आज कई लोग शॉपिंग के लिए शॉपिंग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस कार्ड से ग्राहकों को ब्रांड पर भी ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप भी शॉपिंग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस कार्ड के फायदे क्या है?

नई दिल्ली। अगर आपको शॉपिंग करना काफी पसंद है तो आप शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के जरिये अतिरिक्त लाभ पा सकते हैं। कई लोग शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के जरिये इस्तेमाल करना काफी पसंद करते हैं। इस कार्ड में रेगुलर क्रेडिट कार्ड से ज्यादा लाभ मिलता है। इस कार्ड में आपको रिवॉर्ड प्वाइंट्स, स्पेशल बोनस और स्पेसिफिक ब्रांड पर ज्यादा डिस्काउंट जैसे ऑफर मिलते हैं। इसके अलावा इस पर ईएमआई की भी ऑप्शन मिलता है।

आज हम आपको बताएंगे कि शॉपिंग क्रेडिट कार्ड पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान

इस कार्ड पर रेगुलर क्रेडिट कार्ड की तरह ही ब्याज दर, लेट फीस, पेनल्टी लगती है। ऐसे में अगर आपके पास यह कार्ड है तो आपको लेट पेमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है।

इसके अलावा इस कार्ड पर जॉइनिंग फीस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, लेट पेमेंट फीस, एनुअल परसेंट रेट, ओवरड्यू पेमेंट और ओवर लिमिट फीस आदि कई चार्ज भी लगते हैं। आपको शॉपिंग क्रेडिट कार्ड खरीदते समय इन चार्ज के साथ नियम व शर्तों का भी ध्यान रखना चाहिए।

यह भी जानें

इस कार्ड पर आपको 50 दिनों का इंट्रेस्ट फ्री पीरियड का लाभ मिलता है। इसका मतलब है कि आप जब बिल जनरेट होता है तो आपको पास 3 हफ्ते का समय होता है कि आप इस समय तक बिल का भुगतान कर सकते हैं।

इस कार्ड पर रेगुलर क्रेडिट कार्ड की तुलना में रिवॉर्ड प्वाइंट्स जल्दी मिलते हैं। इन प्वाइंट्स को आप तेजी से रिडीम कर सकते हैं।

इस तरह के कार्ड पर बैंक का ब्रांड के साथ टाई-अप होता है। ऐसे में आपको कुछ स्पेशल ब्रांड पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। आप सेल और डिस्काउंट के मौके पर डबल छूट का लाभ उठा सकते हैं।

इस कार्ड पर आप आसानी से ईएमआई का लाभ पा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको बिल का भुगतान करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना होगा।

लिस्ट होगा जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर, 37 गुना हुआ था सब्सक्राइब

JSW Infra IPO का शेयर 3 अक्टूबर को लिस्ट होगा।T+2 टाइमलाइन में लिस्ट होने वाला ये दूसरा आईपीओ होगा। इससे पहले केवल आरआर काबेल का ही आईपीओ T+2 टाइमलाइन पर लिस्ट हुआ है। एसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर कर खुला था। इसका इश्यू साइज 2800 करोड़ रुपये का था और ये पूरा फ्रैश इश्यू था।

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर मंगलवार (3 अक्टूबर, 2023) को लिस्ट हो सकता है। T+2 टाइमलाइन में लिस्ट होने वाला ये दूसरा आईपीओ होगा। इससे पहले केवल आरआर काबेल का ही आईपीओ T+2 टाइमलाइन पर लिस्ट हुआ है। बता दें, बाजार नियामक सेबी की ओर से एक सितंबर से आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए T+3 टाइमलाइन को ऐच्छिक रूप से लागू किया है। यह नया नियम एक दिसंबर, 2023 से आईपीओ लाने वाली सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा।

JSW Infra IPO 37 गुना भरा

जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर कर खुला था। आईपीओ का अलॉटमेंट 28 सितंबर को फाइनल हुआ था।

ये 2800 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू 37.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों के लिए तय किया गया कोटा 10.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी के लिए निर्धारित कोटा 57.09 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एनआईआई के लिए रिजर्व कोटा 15.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये पूरा फ्रैश इश्यू है। यानी आईपीओ में मिलने वाला सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 113 रुपये से लेकर 119 रुपये तय किया गया था। इसका लॉट साइज 126 शेयरों का है। जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज (इंडिया), डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार है।

डीमेट अकाउंट में चुटकियों में ऑनलाइन भरें नॉमिनी, फॉलो करें ये प्रोसेस

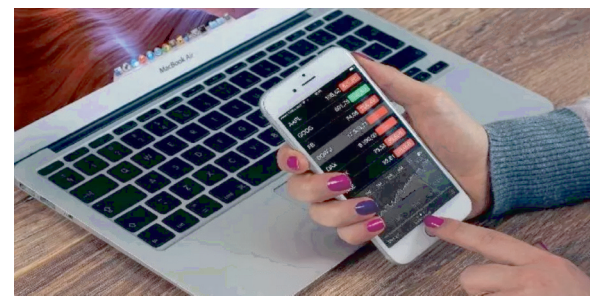

डीमेट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज करना सेबी की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 31 दिसंबर2023 के बाद आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। डीमैट खाताधारक के परिवार का सदस्य दोस्त या उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति भी नॉमिनी हो सकता है। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी अपने डीमैट खाते में दर्ज कर सकते हैं।

नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से सभी डीमैट खातों में 31 दिसंबर, 2023 तक नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि अगर डीमैट खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्तियों को आसानी से उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके।

किन खाताधारकों को नॉमिनी भरना अनिवार्य?

वे डीमैट खाताधारक जिनके पास अपना व्यक्ति डीमैट अकाउंट ने उन सभी लोगों के लिए नॉमिनी भरना आवश्यक है। संयुक्त डीमैट खाताधारक भी नॉमिनी भर सकते हैं। हालांकि, गैर-व्यक्तिगत खातों में नॉमिनी भरना संभव नहीं है।

कौन हो सकता है नॉमिनी?

डीमैट खाताधारक के परिवार का सदस्य, दोस्त या उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति भी नॉमिनी हो सकता है। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट में संपत्ति में अनुपात तय करना होगा।

नॉमिनेशन प्रोसेस

नॉमिनेशन फॉर्म आसानी से आप अपनी डीपी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने डीमैट अकाउंट का नंबर और निजी जानकारी देनी होगी। साथ ही डीमैट खाताधारक को उसका व्यक्ति का नाम, उससे रिश्ता, जन्मतिथि और पता आदि बताना होगा, जिसे वह नॉमिनी बनाना चाहता है। वहीं, अगर नॉमिनी एक से ज्यादा है तो संपत्ति में उनका अनुपात भी तय कर सकते हैं।

ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे भरें?

आप आसानी से डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनेशन भर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगा। इसके बाद आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। फिर डीमैट अकाउंट में आपका नॉमिनी दर्ज हो जाएगा।

अपडेट हुई पेट्रोल-डीजल की कीमतें, दिल्ली से मुंबई तक क्या है लेटेस्ट रेट

तेल वितरण कंपनियों की ओर से प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। ब्रेंट क्रूड 0.17 प्रतिशत या 0.16 डॉलर प्रति बैरल बढ़कर 92.36 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतें पहले की तरह लगभग सभी बड़े शहरों में समान बनी हुई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आखिरी बार कीमतों में बदलाव 2022 में हुआ था।

नई दिल्ली: पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता: पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर
मुंबई :पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई:पेट्रोल 102.74 रुपये और डीजल 94.33 रुपये प्रति लीटर
बड़े महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
नोएडा: पेट्रोल 96.76 रुपये और डीजल 89.93 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम:पेट्रोल 96.97 रुपये और डीजल 89.84 रुपये प्रति लीटर
पटना: पेट्रोल 107.54 रुपये और डीजल 94.32 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ: पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर
जयपुर: पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद: पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर

व्यापारी सम्मेलन में जी एस टी सरलीकरण को लेकर करदाता लामबंद व्यापारियों का शोषण रोका जाए : व्यापार मंडल

(साहिल बेरी)

अमृतसर पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ एवंम्महामंत्री समीर जैन ने बताया की मंडल द्वारा ४ मृतसर में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विशेष तौर पर नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार के चेयरमैन सुनील सिंगही एवंम्-सुनील मेहरा मेंबर नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड एवंम्महामंत्री पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने शिरकत कर व्यापारियों की समस्याओं को सुना एवंम्-इसके समाधान के लिए बोर्ड द्वारा प्रयास का आश्वासन दिया। व्यापारी सम्मेलन में मंडल की ज़िला इकाइयों के साथ। मृतसर की 42 व्यापारी संगठनों ने भाग लिया। व्यापारी सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर सरकार को ध्यान

देने को कहा गया:

1. जी एस टी थ्रेशहोल्ड सीमा के संदर्भ में: जिन फर्मों की वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, उनमें से कुल जी एस टी पंजीकरण का 84 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन उनका कर संग्रहण में केवल सात प्रतिशत योगदान है। इसलिए वस्तु और सेवा कर परिषद को जी एस टी की छूट सीमा को वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, जि व्यवस्थापन में आसानी हो सके। यह नई सीमा GST प्रणाली पर भार को कम करेगी, जिसमें 8 ब 1.4 करोड़ करदाताओं के बजाय केवल 23 लाख करदाता शामिल होंगे।

2. व्यापारी विकास के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम: नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की जानी चाहिए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य व्यापारी और उद्योगपतियों दोनों को उनके व्यवसायों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन, उद्योग ज्ञान और रणनीतिक सलाह प्रदान करना होना चाहिए।

3. जी एस टी की सरलीकरण: वस्तु और सेवा कर जी एस टी एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन इसकी जटिलता बहुत सारे व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। नेशनल ट्रेडर्स बोर्ड से नुरोध किया गया कि वे संबंधित । धिकारियों के साथ मिलकर जी एस टी प्रक्रिया और विधियों को सरलीकृत करने के लिए प्रयत्न करें ताकि छोटे व्यवसायों के लिए 8 नुपालन सुगम हो सके और जी एस टी दरों को कम किया जा सके।

4. जिले के स्तर पर व्यापार बोर्ड के सदस्यों की वृद्धि: प्राथमिक स्तर पर बेहतर प्रतिनिधित्व और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्यों और समितियों की संख्या को जिले के स्तर तक बढ़ाना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर और अधिक स्थानीय निर्णय लिया जा सकेगा और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारी और उद्योगपतियों को प्रतिष्ठानुपूर्ण चुनौतियों का सही से सामना करने में मदद मिले।

5. कॉर्पोरेट सेक्टर और एम एस एम ई व्यापारी के बीच आयकर स्लैब का भेदभाव:

वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आयकर स्लैब दर को 30% से 22% तक कम किया गया परन्तु आयकर स्लैब एल एल पी एच यू एफ और

पार्टनरशिप कंपनियों के लिए 30% ही है इस भेदभाव को समाप्त सभी कंपनियों के लिए आयकर स्लैब 30 प्रतिशत

निर्धारित किया जाए।

6. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा योजना: वरिष्ठ व्यापारी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाए, जैसे कि यूएसए, यूके और कैनाडा में होता है, जहां सरकार वित्तीय मदद प्रदान करती है वरिष्ठ नागरिकों को जिन्होंने व पने

व्यवसाय या सेवा के माध्यम से योगदान किया है। एक व्यापारी जो। पने देश के विकास के लिए आयकर, जी एस टी और

विभिन्न ।न्य करों के रूप में लाखों और करोड़ों रुपए दे रहा है, उसे 65 वर्ष की आयु के बाद राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत पेंशन सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ४ गर उसका व्यवसाय टूट जाता है, तो उसके पास आयु बढ़ने के बाद जीवन बिताने के लिए कुछ भी नहीं होता।

7. व्यापारी वर्ग के लिए मजबूत बीमा योजना: एम एस एम ई व्यापार क्षेत्र में शामिल व्यक्तियों के लिए एक मजबूत बीमा योजना लागू की जाए। 10 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस जी एस टी पंजीकृत और आयकर करदाता के परिवार के लिए होनी चाहिए।

8. समान बिजली दरें: देश में व्यापार और उद्योग के लिए एक बिजली दर होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक टैरिफ की जरूरत है

इंडस्ट्री के साथ कमर्शियल बिजली दरें एक सामान की जाए।

9. पंजाब के सीमा जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज: पंजाब के तरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों के लिए हिमाचल एवंम्जम्मू

कश्मीर की तर्ज पर आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए।

10. राष्ट्रीय व्यापारियों की नीति के संदर्भ में: भारत में व्यापार को बढ़ावा देने और उन्हें आधुनिक व्यापार और ई-कॉमर्स के साथ

प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक व्यापारी नीति का संपूर्ण निर्माण महत्वपूर्ण है। इस नीति में प्रौद्योगिकता। पनाने के लिए वित्तीय

सहायता, डिजिटल ग्राहक सशक्तिकरण प्रशिक्षण, और बाजार पहुंच शामिल होना चाहिए। विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करने, और सस्ते क्रेडिट की पहुंच प्रदान करने में यह नीति सहायक होना आवश्यक है। डेटा सुरक्षा, बाजार सुधार, बुनियादी ढांचा विकास, और 8 नुसंधान और विकास को समर्थन की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इन माध्यमों के माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक व्यापार को संतुलित करने से केवल पारंपरिक व्यापारियों को ही नहीं उधारने, बल्कि समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

11. व्यापारीयों के लिए बैंक व्याज सब्वेंशन: व्यापारीयों के लिए 2% बैंक ब्याज सब्वेंशन दिया जाना चाहिए, एम एस एम ई ट्रेडर की एन पी ए दर न्यूनतम स्तर पर है। गर इसे कॉर्पोरेट के एन पी ए (नॉन परफार्मिंग एसेट) से तुलना की जाए तो नामांतर है, देश में रोज़गार का मुख्य साधन एम एस एम ई ट्रैडर है तो इसे बढ़ावा देने हेतु इनकी उन्नति के लिए इन्हें सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सौम्या की बेटी तानिया पटनायक अखबार की नई संपादक बनीं

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर: जब तक देश में महिलाओं के नेतृत्व और उन्हें सत्ता सौंपने की बात चल रही है, ओडिशा के प्रमुख मीडिया आउटलेट 'संबाद' ने अपना नेतृत्व बदल दिया है। इस अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित घोषणा के अनुसार, समाचार के संस्थापक और संपादक सौम्यरंजन पटनायक ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालाँकि, आज प्रकाशित अखबार की प्रिंटर लाइन में संपादक का नाम भी बदल गया है। यानी आज से वह समाचार में प्रकाशित सभी खबरों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है। 4 अक्टूबर, 1984 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सौमरंजन पटनायक ने 'संवाद' प्रकाशित किया। उन्होंने स्वयं को संपादन से दूर रखा। उस समय समाचार के संपादक के रूप में प्रमुख साहित्यकार सुरेंद्र मोहंती कार्यरत थे। बाद में, सम्पद महापात्र, जो एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विज्ञान के व्याख्याता थे और कुछ वर्षों के लिए पत्रकारिता में आए, ने भी इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया। शुरुआती दौर में संपादन और प्रकाशन तथा प्रबंधन की अलग-अलग जिम्मेदारी देखने वाले सौम्यरंजन ने कुछ दिनों के बाद ओडिशा की पारंपरिक प्रथा को अपनाते हुए संपादक, प्रकाशक और अध्यक्ष की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कई दिनों से संबंधित संगठन और ओडिशा की जनता

इसके परिणाम देख चुकी है। आज समाचार समूह के अध्यक्ष पद से अचानक निलंबन और कुछ ही दिनों में उनके राजनीतिक जीवन में आए तूफान से संगठन में सरकार द्वारा 'समाचार' के प्रबंधन में एक नए गणित की संभावना भी बनती है। श्री पटनायक ने इस अखबार को लॉन्च करते हुए कहा था कि 'बासी अखबारों का युग खत्म हो गया है.' वह 4 तारीख को 40 साल के होने जा रहे हैं. आज यह अखबार प्रदेश में एक प्रभावशाली मीडिया के रूप में खड़ा है।

टीएमसी का राज घाट दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

शम्स आगाज़ जामेई

नई दिल्ली। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन आवंटित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिस में टीएमसी के महा सचिव अभिषेक बनर्जी, मंत्री फरहाद हकीम, सांसद महुआ मित्रा, शम्स इक़बाल सहित सांसदों, और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। टीएमसी ने इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को 'फाइट फॉर राइट' नाम दिया गया है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी जयंती पर राजघाट दिल्ली पर जमा हुए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन आवंटित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा, आवास योजना और अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य को धन का वितरण नहीं किया गया। और केंद्र सरकार के खिलाफ़ लड़ाई जारी रखने की चेतावनी भी दी।

भीलवाड़ा एनसीसी कैडेट ने राजस्थान के पौराणिक धरोहर,मंदिर की स्वच्छता का चलाया अभियान

अनूप कुमार शर्मा, भीलवाड़ा। स्थानीय पांच राज स्वतंत्र कंपनी एनसीसी भीलवाड़ा के एनसीसी कैडेट ने स्वच्छ भारत अभियान एवं महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष में स्वच्छता अभियान चलाया ।एनसीसी यूनिट कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तजेंद्र शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा एनसीसी यू ट के कैडेट ने विभिन्न टुकड़ियों में स्वच्छता अभियान के तहत पौराणिक मंदिर, तालाब, एनसीसी यूनिट , धार्मिक स्थल, शास्त्री नगर स्थित मंदिर, सार्वजनिक स्थल , डबोक स्तिथ शिव मंदिर आदि स्थल पर वहां पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए सफाई करी एवं कूड़ा करकट एवं गंदगी को र क स्थान इकट्ठा किया। सभी एनसीसी कैडेट ने पुराने मंदिर, पौराणिक धरोहर आदि को स्वच्छ रखने की शपथ भी ली ।स्वच्छता के इस अभियान के माध्- से राजस्थान की धरोहर , मंदिर आदि को स्वच्छ रखने में भीलवाड़ा के एनसीस कैडेट ने एक जोरदार पहल की है ।एनसीसी कैडेट भावेश तुलचानी, केशव सिंह राठौर, रोशन गुर्जर का विशेष योगदान रहा ।लेफ्टीनेंट राजकुमार जैन, लेफ्टीनेंट संजय गोदारा, सूबेदार जसपाल , सूबेदार सोहन सिंह , प्रदीप सिंह आदि के नेतृत्व में टुकड़ियों में एनसीसी कैडेट सफाई अभियान चल रहे है।

मीरा ने गांधी जयंती को स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया

अनूप कुमार शर्मा , भीलवाड़ा । मीरा अध्यक्ष मंजु बापना ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजु पोखरना के सानिध्य में आज 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती मनाई गई व बास्केट बॉल ग्राउण्ड में गांधी जी के मूर्ति को माल्यार्पण कर सफ़ाई अभियान चलाया गया ।सचिव कला कुदाल ने बताया कि बास्केट बॉल खेलने वाले बच्चो को खाने के पेकेट फल व बिस्किट वीरा शिल्पी माथुर व मंजु पोखरना के सहयोग से वितरण किए गए। सभी बच्चो को गंदगी नहीं फैलाने व कचरा डस्टबीन में डालने हेतु प्रेरित किया गयाकार्यक्रम में मंजु पोखरना, मंजु बापना, कला कुदाल, अशोक जैन, कपिल शर्मा, विजय बाबेल, शबनम डायर आदि उपस्थित थे।

रामलीला मैदान में उमड़ा कर्मचारियों का सैलाब, सब ने एक सुर में कहा - लोकसभा चुनाव में चलेगा वोट फॉर ओपीएस

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देश के हर कोने से शिक्षक व कर्मचारियों का रेला सुबह होते ही रामलीला मैदान पर पहुंचना शुरू हो गया। दिल्ली की सभी सड़कों पर एनएमओपी एस/अटेवा की टोपी लगाकर शिक्षक व कर्मचारियों ने अनुशासित ढंग से दिल्ली वासियों का दिल जीत लिया। जिस पर टोपी लगाए रेलवे स्टेशन पर पेंशनविहीनों की भारी भीड़ हो गई जिसके कारण रेलवे स्टेशन से निकलना मुश्किल हो गया।

दिल्ली की सड़कें जाम हो गईं। हर तरफ शिक्षक व कर्मचारी अटेवा/एनएमओपीएस की टोपी लगा कर पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन से रामलीला मैदान की ओर से बढ़ते रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों शिक्षक कर्मचारियों ने एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनएमओपीएस जिंदाबाद, अटेवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।

अलग राज्यों के कर्मचारियों ने अपने-अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। तमाम कर्मचारियों ने 'जो ओपीएस बहाल करेगा, वही देश पर राज करेगा' की टी-शर्ट पहन कर पुरानी पेंशन बहाली के नारे लगा रहे थे और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। रामलीला मैदान की तैयारी दिल्ली एनएमओपीएस के संरक्षक डीएन सिंह ने संभाल रखी थी तथा मंच को तैयार करने का काम बखूबी किया।

एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पेंशन शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर सकते हैं तो विश्व में आज भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है तो वह अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता है। अगर सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की तो आने वाले चुनाव में वोट फ़ॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे।

एनएमओपीएस के राष्ट्रीय महासचिव स्थित

प्रज्ञ ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिये पूरा देश एकजुट हो गया है। अब देश का शिक्षक व कर्मचारी जाग गया है वह पेंशन लेकर ही रहेगा। चाहे उसके लिये उसे कुछ भी करना पड़े ।रैली का सफल संचालन एनएमओपीएस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने किया। एनएमओपीएस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा था। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने पुरानी पेंशन बहाल कराने की शपथ ली थी और उन्होंने अपनी शपथ पूरी की।

राजस्थान एनएमओपीएस के प्रदेशाध्यक्ष कोजाराम सियाग ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन बहाल कर पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन जीवन मरण का प्रश्न है इसलिए हरियाणा में होने वाले चुनाव में कर्मचारी पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाएगा। एनएमओपीएस उड़ीसा के सुशांत पांडा ने कहा कि दिल्ली में पूरे देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिये जो एकजुटता दिखाई है इसी एकजुटता से पुरानी पेंशन बहाल होगी। पंजाब से एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत सिंह ने कहा कि आज रामलीला मैदान पर उमड़ी भीड़ प्रधानमंत्री जी को पुरानी पेंशन बहाल करने पर मजबूर कर देगी।

दिल्ली जीएसटीए महासचिव अजयवीर यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली में दिल्ली ने हमेशा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और पुरानी पेंशन के लिये भारत सरकार पर पूरा दबाव बनाकर पेंशन बहाल कराएगा। स्वास्थ्य महासंघ के अशोक कुमार ने कहा कि अटेवा /एनएमओपीएस ने देश के राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करवाकर सराहनीय कार्य किया है।

अटेवा/एनएमओपीएस के कारण ही आज पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है। सिक्किम एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष पेमा खांडू ने कहा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए कहा कि हम अपने राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बिहार एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय ने कहा कि एनएमओपीएस द्वारा बिहार से शुरू की गई एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का असर बिहार सरकार पर इतना पड़ा है कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन पर अपना रुख सकारात्मक दिखाया है।

रेलवे फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस के अमरीक सिंह व राजेन्द्र पाल ने कहा कि रेलवे का कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाल करा कर ही दम लेगा। उप्र लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राममूरत यादव ने कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजी सरकार भी अपने मुलाजिमों को पेंशन देती थी और आजादी के बाद हमारी पेंशन छिन गयी। स्वास्थ्य महासंघ के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार ने कहा कि पेंशन हर शिक्षक व कर्मचारी का अधिकार है हम इसे लेकर रहेंगे।

एनएमओपीएस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कर्नाटक इकाई के शांताराम तेजा ने कहा कि कर्नाटक में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर ही सरकार बदली है। आईएनएमओपीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। पेंशन शंखनाद रैली को समर्थन देने के दिन सुबह से ही विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं का तांता लगा रहा।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाकपा माले के महासचिव काम. दीपंकर भट्टाचार्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली, यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय कुमार लल्लू, सपा उप्र से एमएलसी लाल बिहारी यादव, डॉ. मान सिंह यादव, एक्टू महासचिव काम. राजीव डिमरी, किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बसपा से लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव, महाराष्ट्र जूनी पेंशन के एमएलसी सुधाकर अड़वाले, इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडेय व महासचिव सर्वजीत सिंह, नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे, राष्ट्रीय प्रचार सचिव -डॉ कमल उसरी भारतीय किसान यूनियन के राकेश सिंह टिकैत ने रैली को संबोधित कर पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया और सभी ने एक सुर में कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे।

लायन्स क्लब भीलवाडा ने दिव्यांगजनो के लिए उपकरण वितरण शिविर में 350 भोजन पैकिट वितरण कर मानव सेवा की

अनूप कुमार शर्मा , भीलवाड़ा। महात्मा गांधी व लाल बहादुर की जयंती के अवसर पर लायंस क्लब भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद टाउन हॉल में सरकार की ओर से आयोजित दिव्यांगजनों को साइकिल एवं उपकरण वितरण समारोह में मानव सेवा के तहत 350 दिव्यांग जनों सहित जरूरतमंदो को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। लायन सचिव बालकिशन कालिया ने बताया कि इस सेवा कार्य में लायन एल बी रांका, सुधीर राठी, पवन पवार, ललित सांखला, कोषाध्यक्ष आनंदीलाल चौधरी द्वारा कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाकर पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

राकेश शर्मा आईएनएस के प्रेजिडेंट चुने गए

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। दैनिक समाचार पत्र समूह 'आज समाज' के राकेश शर्मा को भारत में समाचार पत्र पत्रिकाओं के शीर्ष संगठन दि इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटीज (आईएनएस) का अध्यक्ष चुना गया है।

आईएनएस की 84 वीं वार्षिक महासभा की बैठक के बाद उन्हें अध्यक्ष पद पर चुना गया है। बता दें कि बैठक में 2023-24 के लिए संगठन की नई कार्य समिति का भी चुनाव किया गया।

इस चुनाव में मातृभूमि के एमवी श्रेयांस कुमार को सहायक अध्यक्ष और सन्मार्ग के विवेक गुप्ता को उपाध्यक्ष चुना गया है। अमर उजाला के तन्मय माहेश्वरी को अवैतनिक कोषाध्यक्ष चुना गया है। वहीं मेरी पॉल को महासचिव चुनाव गया है।

आईएनएस की वार्षिक बैठक में नयी कार्यकारिणी के 41 सदस्यों का भी चयन किया गया है। अध्यक्ष राकेश शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि कोरोना से जूझने के बाद इंडस्ट्रीज तेजी से वापसी कर रही है। इंडस्ट्रीज को आगे बढाने का अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। मैं इसे आगे बढाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना सुनिश्चित करूंगा।

गांधी शास्त्री की जीवनी को आत्मसात करने की प्रेरणा दे, नवाचार ने दिलाई बाल विवाह नहीं करने की शपथ

महेंद्रगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाई गांधी व शास्त्री जयंती

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाडा। महेंद्रगढ़ (बागौर) स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देश को सत्य, अहिंसा एवं स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रकाश डालते हुए उनकी जीवनी को आज के युग के बच्चों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी गई। साथ ही इस अवसर पर नवाचार कॉर्डिनेटर लीना पारीक ने बाल विवाह पर विस्तार से समझाते हुए छात्र-छात्राओं को बाल विवाह नहीं करने की शपथ भी दिलाई।

संस्था के उपाचार्य पीयूष चंदेल ने विद्यार्थियो को अपने जीवन में शास्त्री एवं गांधी जैसे महापुरुषों के विचारों, आदर्शो एवं मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित करते हुए बताया कि गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती पर विद्यालय में निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 12 के छात्र रणजीत एवं पोस्टर प्रतियोगिता में कक्षा 12 के छात्र सुरेश सुथार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

सुरेश चंद्र बुलीवाल ने बताया कि नवाचार संस्थान के तत्वाधान में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम में सांवरमल जोशी एवं हंसा कंवर राणावत ने संगीतमय गीत की प्रस्तुति देकर बच्चों को प्रेरित किया।

नवाचार संस्थान की कॉर्डिनेटर लीना पारीक ने बताया कि नवाचार सचिव अरुण कुमार कुमावत व जिला कॉर्डिनेटर जितेंद्र कुमार के निर्देशन में बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में महेंद्रगढ़ विद्यालय के छात्र छात्राओं को विस्तृत जानकारी प्रदान कर बाल विवाह नहीं करने को लेकर शपथ भी दिलाई गई । इस अवसर पर पत्रकार विष्णु विवेक शर्मा ने इन महापुरुषो के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शो को अपने जीवन मे आत्मसात करने हेतु प्रेरित किया।

कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता कैलाश चंद्र जोशी ने किया।

इस अवसर पर मधुबाला राठी, मंजू नेनावटी व हंसा कँवर राणावत, व्याख्याता मुकेश सिंह बड़वा, रवि कुमार शर्मा, रेणु सुरेला, गोपाल लाल जीनगर, मुकेश चंद्र जोशी, प्रहलाद राय दोनी, मंजू बूलीवाल, जयप्रकाश टेलर, हेमेंद्र सिंह चारण एवं विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959. (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023